THE VICE-CHAIRMAN (Shri R. R. MORARKA): The Leader of the House to introduce the Minister.

Introduction of Minister

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, as you know, while introducing the new Ministers, the Prime Minister mentioned that Mr. V.C. Shukla was not present. May I have your permission to introduce Shri V. C. Shukla, Minister in charge of Civil Supplies?

SOME HON. MEMBERS: He does not need any introduction.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri R. R. MORARKA): Let us have the Calling Attention Motion.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Steep Rise in Prices of Essential Commodities and their Non-Availability in the Open Market

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Uttar Pradesh): Sir, I beg to call the attention of the Minister of Civil Supplies to the steep rise in prices of essential commodities including sugar, edible oils and pulses and their non-availability in the open market and the steps taken by Government in this regard.

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES (SHRI V. C. SHUKLA): Sir, the Government shares the concern of the House about the rise in the prices of some of the essential commodities. The localised shortage of some essential commodities like sugar, pulses and edible oils has to be tackled vigorously.

The inflation is due to the cumulative impact of several factors. Apart from the unsound fiscal and monetary policies followed in last three years, the country has witnessed an unprecedented drought which has affected very large parts of the country besides causing a sizeable shortfall in the production of agricultural commodities including foodgrains, oilseeds and sugarcane. The administered prices of several commodities like petroleum products, cement, steel and coal were raised. The import prices of several commodities like cement and steel went up in the international market. The situation has been further aggravated by severe difficulties in transport and power sectors affecting production of essential commodities and their movement.

A number of measures have been taken by Governemnt in last six months to improve the situation. The monthly releases of cereals from the Central pool, free-sale sugar and imported edible oils for sale through the public distribution system have been stepped up substantially. Import of edible oils is being continued and it has been decided to import a limited quantity of sugar. Forward trading in gur has been suspended and margins on bank advances against gur and khandsari have been raised. There has been a significant increase in the number of fair price shops, particularly in the drought affected States. As there is very little scope for importing pulses, efforts are being made to increase their production. The supply of kerosene to States has been raised. Several measures have been taken to improve the movement of essential commodities by Railways.

The provisions of the Essential Commodities Act and the orders issued thereunder as well as the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 are being enforced by the States vigorously.

Government is giving high priority to supply management and measures for controlling prices. Hon'ble Members will appreciate that this would call for co-operation of all of them irrespective of party affiliations.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : श्रीमन्, मंत्री महोदय का वक्तव्य सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ और लगता यह है कि वे कहीं किसी मिथ्या महल में रह कर वक्तव्य दे रहे हैं। उन्होंने वक्तव्य में कहा कि कमी स्थानीय है। उसी संदर्भ में उन्होंने चीनी का भी उल्लेख किया; फिर यह कहा है कि पिछले 3 वर्ष की जो गलत नीतियां रही है उनके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 3 साल पहले, जब जनता सरकार थी, उस समय चीनी का भाव क्या था और आज चीनी के भाव क्या हैं? उस समय गुड़ के भाव क्या थे, आज गुड़ के भाव क्या हैं, उस समय प्रसाधन की वस्तुओं के भाव क्या थे, आज प्रसाधान की वस्तुओं के भाव क्या है; आज दवाइयों के भाव क्या हैं और उस समय क्या थे तो पता लगेगा अब कि 40–50 प्रतिशत कीमतें बढ़ी हैं।

चीनी का उन्होंने बड़े साहस के साथ उल्लेख किया है। आज आप को दिल्ली के बाजार में साढे 6,7 रुपये किलो से कम कीमत पर चीनी नहीं मिलेगी, बल्कि 7 और 8 कीमत होगी। यह क्यों हुआ है? मंत्री महोदय बताना भूल गये, उन्होंने कहा कि बहुत कम तादाद में हम बाहर से चीनी खरीद रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या चुनाव के दिनों उन्होंने विदेशों से चीनी नहीं खरीदी? उन्होंने थाइलैंड से चीनी खरीदी थी। उन को यह भी मालूम होगा कि थाइलैंड में खुले बाजार में उसी स्थान पर क्या रेट था और सरकार से सरकार के लेने का क्या रेट था? मैं जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि थाइलैंड में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रेट 100 डालर प्रति क्विन्टल था और आन दि स्पाट 515 डालर प्रति क्विंटल था। हमारी सरकार ने आन दि स्पाट खरीद की––इतना बड़ा अन्तर था, जिस में करोड़ों रूपयों का नुकसान हुआ। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह उन्होंने चुनाव के दिनों में क्यों किया? बात खुली हुई है। एक तरफ उन्होंने चीनी इम्पोर्ट की और वह चीनी जो यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहीं चीनी समुद्री मार्ग में ही फिर खरीद कर वापस ली गयी। थाइलैंड की चीनी एजेन्ट की मार्फत खरीदी गयी क्यों कि चुनाव के लिये इन को पैसा चाहिये था।

एक और देखने योग्य बात है जब कभी चुनाव के अवसर पर श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता में होती हैं उस समय कीमत तीन गुनी, चार गुनी, दस गुनी बढ़ जाती है। कोई चुनाव ले लीजिये। चुनाव के पहले साबुन की शक्ल दिखाई देती थी, अब नहीं दिखाई देती। प्रसाधन वस्तुओं की, दवाइयों की, कागज की, हर चीज की कीमतें चुनाव काल से कम थी, खास तौर से ऐसी चीजों की जो मल्टीनेशनल कम्पनियां बनाती है। मेरी जानकारी है कि मल्टीनेशनल कम्पनियों से भी पैसा लिया गया। उसके बदले उन्हें छूट दी गई कि चुनाव के दिनों के बाद कीमतें बढ़ा लीजिये इस लिये यह कीमतें बढ़ी हैं। यह फेनोमेना आज का नहीं है हर चुनाव का है। उन्हों ने कहा कि इन्टरनेशनल मार्केट की कीमतों का असर पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं कि लीवर ब्रदर्स की साबुनों पर कौन से इन्टरनेशनल मार्केट का असर पड़ा है। गुड की कीमतों पर कौन से इन्टरनेशनल मार्केट की कीमतों का असर पड़ा है। फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ी है। कल हमारे नेता आडवाणी जी ने सवाल उठाया था कि संसद के सत्र के एक-दो दिन पहले तेल की कीमतें क्यों बढ़ाने की घोषणा की गयी। अगर यहां घोषणा सदन में करते तो जाबाब देना पड़ता। इस बार फर्टिलाइजर को भी छोड़ा नहीं है। फर्टिलाइजर ऐसी चीज है जिस का काश्तकार उपयोग करता है। खुद

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

सरकार ने कहा है तेल की कीमतें बढाने के समय फर्टिलाइजर की जो कीमत बढ़ रही है उस में हम किसानों को 25 परसेंट, 30 परसेंट छूट देना चाहते हैं। लेकिन कीमतें अगर 100 की 150 हुई है तो 33 परसेंट, 35 परसेंट सब्सीडाइज करने के बाद भी काश्तकार को पहले की अपेक्षा ज्यादा देना ही पड़ेगा।

आप ने जनता सरकार की बात कही है। जनता सरकार के समय जितनी फर्टिलाइजर की खपत हुई, जितना खाद उपयोग में लिया गया वह एक रिकार्ड है। पिछले 40 साल के अन्दर रेकार्ड है क्योंकि जनता सरकार ने खाद के ऊपर काफी ड्यूटी कम कर दी। हमने खेती सम्बन्धी हर चीज में छूट दी थी। लेकिन आज किसान को पता है कि डीजल उस को मिलेगा नहीं, खाद मिलेगी नहीं और कीमतें चढ़ती जा रही हैं। दिखाई देता है कि यह सरकार येनकेन प्रकारेण राज्य करना चाहती है चाहे कीमतों का कुछ भी हो और किसान कितना भी मरे।

इसलिए मैं पूछना चाहता हूं (1) थाइलैंड से इन्होंने आन दि स्पाट क्यों खरीदी एजेन्ट कौन थे और उस एजेन्ट को इन्होंने कितना कमीशन दिया है ? इसी प्रकार से यह आरोप कि जो हमारी चीनी बाहर जा रही थी वही समुद्र के रास्ते वापस खरीदी गयी, कहां तक सत्य है ? दूसरे लीवर ब्रदर्स जैसी जो बीसियों मल्टीनेशनल कम्पनियां है उनकी वस्तुओं की कीमत चुनाव के समय और अब क्यों बढ़ी है ?

मेरी जानकारी के अनुसार लीवर ब्रदर्स से और दूसरों से उन्होंने पैसा लिया है। इस का वह स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। तीसरे फर्टिलाइजर का दाम ज्यादा होने के कारण किसान पर भार पड़ रहा है। उस से किसान दबेगा, और उस के कारण सारे देश में अन्न की कीमतें बढ़ जायेंगी। इस को रोकने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अपनी पार्टी की जितनी भी तारीफ करें उस से मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यह बात सत्य है और इस को रेकार्ड में देखा जा सकता है कि जो कीमतें बढ़नी शुरू हुई वह 1977 के पहले जो कांग्रेस सरकार थी उस समय बढ़नी शुरू नहीं हुई थीं। 1977 के चुनाव के बाद ...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आंकड़े दिखायेंगे ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : 1977 के चुनाव के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी उस के बाद ही यह कीमतें बढ़नी प्रारम्भ हुई थीं और उन कीमतों के बढ़ने में तेजी उस समय आयी कि जब लोकदल की सरकार बनने के कुछ पहले श्री चरण सिंह जी ने अपना बजट पेश किया। उस में कई तरह के प्रावधान किये गये थे और उन की वजह से कीमतें बढ़ीं जिन पर किसी प्रकार से रोक लगाना उस सरकार के लिये मुश्किल हुआ। हम लोगों ने अब कुछ रोक लगायी है और और हम आज जो कार्यवाही कर रहे है उस से आगे चल कर और ज्यादा रोक कीमतें बढ़ने पर लगेगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं।

यह ठीक है कि स्थानीय रूप से कुछ चीजों की कमी है। शक्कर की बात मैं जानता हूं। मध्य प्रदेश में और कुछ दूसरे राज्यों में तो शक्कर की उपलब्धि ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ठीक नहीं है और इस लिये जहां इस तरह की कमी की स्थिति है कुछ चीजों की उस को हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। जो आरोप

माननीय सदस्य ने लगाया कि शक्कर की खरीद में कुछ अनियमितताएं हुई और कुछ गलत ढंग से काम किया गया, उन के लिये मैं कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि वे आरोप मिथ्या हैं और उन में कोई तथ्य नहीं है और इस तरह के आरोप इस प्रसंग में लगाना मैं समझता हूं कि न केवल गलत बात है बल्कि उस चीज को तूल देने की बात है। जिस समय हम कीमतों को ठीक से स्थिर करने और घटाने का प्रयास कर रहे हैं उस समय ऐसे आरोप लगाना जो कि सत्य नहीं हैं, ठीक नहीं है। (*Interruptions*) मेरी बात सुन लीजिए उस के बाद अगर उपाध्यक्ष जी इजाजत दें तो आप अपनी बात कह लीजियेगा। यह आरोप न केवल मिथ्या हैं बल्कि इस तरह की बातों से कीमतों को बढ़ाने में और कालाबाजारी करने वालों को और गैर-कानूनी काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है। इस लिये मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि कृपा कर इस तरह की बातें कम से कम सदन में न करें। राजनीतिक सभाओं में जो कुछ कहा जाता है वह तो अलग बात है, लेकिन सदन में तो जिम्मेदारी की बात होनी चाहिए। (*Interruptions*) भाव के बढ़ने की जो बात है उसके लिये मैंने पहले ही कहा है... (*Interruptions*) भाव जो बढ़े हैं पिछले तीन सालों में वह जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद बढ़े हैं और इसलिये अब हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उस पार्टी की सरकार ने जो जो गलतियां की हैं और जो जो गलत काम किये थे उन में सुधार करें और भावों को स्थिर करें और ऊंचे भावों को नीचे लायें।

चुनाव के दौरान जो बातें की गयी हैं उन के लिये जो कुछ कहा गया है वह भी सही नहीं है और ऐसी बातें करने से और हम लोगों को और देश को कोई फायदा नहीं होगा। मल्टीनेशनल्स की जो बात है कि उन से किसी तरह का गठ-बन्धन किया गया है या उन से कुछ साझेदारी की गयी है इस के बारे में आप को ज्यादा मालूम होगा। हम लोगों के जमाने में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है और न आगे होगी। उर्वरक की कीमतों के बारे में जो आप ने कहा, उस के लिये हम लोगों का प्रयास है कि उस की कीमतें जितनी हम कम कर सकें करें ताकि कृषकों को अधिक फायदा हो और उन को राहत मिले और मुझे आशा है कि हम लोग जो भी प्रयत्न कर रहे हैं उस का फल हम को मिलेगा।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : थाईलैंड के बाजार से जो चीनी उन्होंने खरीदी है उस, की कीमत 51 प्रति क्विंटल डालर है और गवर्नमेंट टु गवर्नमेन्ट जो खरीदी जाती है उस का भाव 100 डालर का है, इस बारे में जो बात मैंने कही थी उस का मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया।

श्री विद्या चरण शुक्ल : नागरिक आपूर्ति मंत्रालय यह खरीद फरोख्त नहीं करता। इसलिये अगर इस का जवाब पूछना हो तो संबित मंत्री से पूछें, उन को उत्तर मिल जायगा।

श्री प्रकाश मेहरोत्रा (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस तीव्र गति से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं उस से न केवल हमें और आप को बल्कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को कठिनाई हो रही है और वह पीड़ित है। मैं समझता हूं कि यह विषय कोई राजनीतिक विषय नहीं है और किसी भी सरकार को इसके लिए चिन्तित होना चाहिए। मेरा अपना अनुमान है कि हमारी सरकार भी जो प्राइसेज बढ़ रही हैं इस के लिए चिन्तित हैं। न केवल सरकार चिन्तित है, मेरा अपना विचार यह है कि जो बहुमत हमको इस असेम्बली के चुनाव में मिला है, उससे हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न भी हो गया है कि हम कीमतों को कम करें।

[श्री प्रकाश मेहरोत्रा]

माननीय मंत्री जी ने कीमतों को कम करने के लिए जो कदम उठाये और जो आंकड़े दिये तो मेरा कुछ ऐसा विश्वास है कि सरकारी आंकड़े जो हैं उन पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। जब-जब इस तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं और कीमतें बढ़ीं तो सरकारी जो आंकड़े दिये गये उनसे यह प्रतीत होता था कि जैसे कीमतें अब आगे नहीं बढ़ने पायेंगी या जो कीमतें बढ़ी भी हैं वह मार्जिनल इनक्रीज हुआ है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से आप देखें तो जब बाजार जाकर आप सामान खरीदते हैं तो दाम हमेशा बढ़ते ही गये। मुझे इस संदर्भ में किसी की लिखी हुई बात याद आ गई कि—

Statistics is like the bikini suit. What it reveals is merely suggestive but what is conceals is vital.

तो मान्यवार, मेरा निवेदन है कि बजाय इन आंकड़ों में जाने के अगर सरकार यह व्यू ले कि वास्तविकता में दाम बढ़ रहे हैं और उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहियें तो उससे हमको तथा देश को ज्यादा राहत मिल जाएगी।

मान्यवर, स्थिति यह है कि जैसे कुछ महीने पहले नौन ब्रैंड था चाय का आधा किलो का दाम करीब 12–13 रु० था और आज उसके दाम 18–19 रुपये हो गया। मैं कुछ ही चीजों का जिक्र कर रहा हूं। ऐडिबुल आयल के दो किलो के टिन का दाम पहले 18 रुपये था, आज वह बढ़कर 36 रुपये में मिल रहा है। ग्राम, बीन, पल्सेज 3 रुपये से 5 रुपये किलो मिलती थीं, आज वह बढ़ कर 6 रुपये और 10 रुपये किलो हो गई। शुगर के बारे में इस सदन में और बाहर भी काफी चर्चा हो चुकी है। 2.15 रुपये से 2.25 रुपये किलो में जो शक्कर बिकती थी वह 7 रुपये और सवा 7 रुपये किलो हो गई है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो सरकार यह कहती है कि हम फेयर प्राइस शाप्स के माध्यम से इन चीजों को बेचेंगे और हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको स्टेंथन करेंगे। जब इस तरह की कठिनाई उत्पन्न होती है तभी सरकार का ध्यान इस तरफ जाता है। आज फेयर प्राइस शाप्स की स्थिति क्या है, वह मैं बतलाता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORAKA): Please put your question. There are so many Members...

SHRI PRAKASH MEHROTRA: Sir, this is an important and burning issue. If you were sitting here and speaking, you would have taken the same time. So I would request you to give me some time ..

मान्यवर, फेयर प्राइस शाप्स में आप सामान लेने जाइये तो वहां सामान नहीं है। वह कहता है दो दिन बाद आइये या टाइम अप हो गया। आप को सामान मिलेगा नहीं। आप किसी आदमी को सामान लेने के लिए भेजिये तो कपड़ा मंगाया तो उस पर्ची पर सब चीजें काट देंगे और वह ब्लैक में बेचेंगे। जो सरकार पावर में रहती है उससे संबंधित लोगों को ये दुकान दी जाती हैं, इसलिए उन पर कड़ाई सरकार नहीं कर सकती। मेरा निवेदन है कि इस तरह की कड़ाई की आवश्यकता है। इसी तरह सामान पर लेबल 8 रु० का लगा है तो बेचते हैं 12 रुपये में। आप उनसे कहिये कि 8 रुपये लिखा हुआ है तो कहेंगे कि यह तो हमारे पास पुराने दाम से चीज आई है, इसलिये 12 रु० में दे रहे हैं, नया लेने जायेंगे तो 15 रु० में मिलेगी। कपड़े पर 4 रु० मीटर लिखा है, लेकिन ले 7 रुपये हैं। वह कहता है इस पर एक्साइज ड्यूटी, सैल्स टैक्स है। तो मेरा निवेदन है कि जो आपकी कंज्यूमर प्राइस हो उसको आप स्टैम्प करें। कंज्यूमर को यह मालूम होना चाहिये कि उसको किस दाम पर कपड़ा मिलेगा। मेरा आपसे यह सुझाव है

कि हम को इस सिच्युएशन को मीट करने के लिये शोर्ट टर्म्स स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, इमीजिएट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे । जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा । जो खास-खास आइटम्स हैं उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से बेचना पड़ेगा । उनको एक सर्टीफिकेट देना चाहिये कि कितना स्टाक रिसीव किया और कितना माल हमने बचा रखा है यानी आज हमारे पास कितना स्टाक है और उनकी प्राइस जो है वह डिसप्ले करनी चाहिये । होता यह है कि एक आदमी राशनकार्ड लेकर जाता है और चार-चार दिन धक्के खाकर आ जाता है । मेरा निवेदन है कि डेटवाइज कार्ड फिक्स कर दें । यह कर दें कि इस नम्बर से ले कर इस नम्बर तक इस डट को राशन लेंगे और इस नम्बर से लेकर इस नम्बर तक इस डेट को राशन लेंगे । जो किसी कारण से न जा पाये तो उसके लिये 15 दिन में से एक डट फिक्स कर दें ताकि जिन्होंने राशन नहीं लिया वे उस दिन आकर ले जायें ।

दूसरा निवेदन यह है कि हम कंज्यूमर की एक कमेटी बना दें । अब होता यह है कि जो कमेटीज हम बनाते हैं उसमें ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर लेते हैं जिनको कभी लाइन में खड़े होना नहीं पड़ा । उसमें जो कठिनाई होती है उसका उनको कोई मौका नहीं मिला । मेरा निवेदन यह है कि कमेटीज ऐसे लोगों की बनाई जाए जो मिडिल इन्कम ग्रुप या लोअर इन्कम ग्रुप के लोग हों जो खुद, उनकी औरतें या उनके बच्चे पूरे दिन भर लाइन में खड़े रहते हैं । उन्हें मालूम होता है कि कठिनाई क्या होती है । उस कमेटी को अधिकार होना चाहिये कि वह नियमों को इम्पलीमेंट करें । उस कमेटी को यह अधिकार होना चाहिये कि जाकर तलाशी ले कि किसके पास कितना स्टाक है और जो लोग लाइन में खड़े रहते हैं उनको क्या कठिनाई है उसकी जानकारी लें और अगर वहाँ कोई चीज गलत हो रही है उस पर इमीजिएट एक्शन लेना चाहिये । आपकी कोई लोंग टर्म प्लानिंग होनी चाहिये । जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि पल्सेज को विदेशों से नहीं मंगा सकते इसलिये हम उसका प्रोड्क्शन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं । मेरा निवेदन यह है कि जो चीजें यहाँ पैदा होती हैं उन सब के लिये यह करना चाहिये । आडिबल आयल है । सन् 1960 में हम सेल्फ सफिशियेंट थे । आज हम को उसका 25 परसेंट इम्पोर्ट करना पड़ता है । 20 साल से जो इंड है वह स्टेगनेंट है । वर्ल्ड में लोएस्ट प्रोडक्शन हमारा है । इस तरह से हमारे जो एक्सपेलर्स हैं, जो कोल्हू हैं, जो बुलक कार्ट से चलते है या इस तरह की ओ सलीट मशीनरी है उससे रिकवरी बहुत कम होती है वैस्टेज ज्यादा होती है उसको मोर्डनाइज करने की जरूरत है । अभी मंत्री महोदय ने कहा हम आडिबल आयल इम्पोर्ट कर रहे हैं । रा-आयल इम्पोर्ट कर रहे हैं । उसका फारेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा होता है इसलिये जो आयल सीड्स हैं उसको इम्पोर्ट करें तो हम फारेन एक्सचेंज की सेविंग कर पायेंगे । और जो अंडरयुटीलाइज कैपेसिटी में हैं उनको युटीलाइज कर पायेंगे ।

आपने एस० टी०सी० को मोनोपली दे दी है इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन एस० टी० सी० को यह चाहिए कि वह बतायें कि उनकी परचेज प्राइस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस क्या है, पैकिंग प्राइस क्या है ? इस की जानकारी वह सब को दें । कुछ पता नहीं लगता कि कास्ट प्राइस क्या है और किस प्राइस वह बेच रहे हैं । इसी तरह से शुगर है । फूड कारपोरेशन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन मशीनरी रही । उसके बाद आपने मशीनरी को डिसमेंटल कर दिया । उसका नतीजा यह हुआ कि दो महीने बाद जो एलोकेशन हुआ

[श्री प्रकाश मेहरोत्रा]

बह पहुंच नहीं पाया । उसकी प्राइस बढ़ गई । इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई लौंग टर्म पालिसी होनी चाहिए । रोज-रोज पालिसी चेंज हो जाती है । पहले आपने फुल कंट्रोल किया । फिर आपने डी-कंट्रोल किया और अब पार्शियल कंट्रोल हो गया है । ये चीजें ऐसी हैं कि जो सरकार के साथ बदलती हैं। मेरा निवेदन है कि ये चीजें सरकार के साथ नहीं बदलनी चाहिए क्योंकि यह परमानेंट नीड की चीजें हैं । सरकार को एडहोकिज्म छोड़ कर लौंग टर्म बेसिस पर कोई पालिसी बनानी चाहिए उसमें मेनुफेक्चरर हों, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर हों, रीटेलर हों, कंज्यूमर हों, रिप्रेजेंटेटिव हों मेजर पोलिटिकल पार्टीज के । इन सब लोगों से सलाह-मश्विरा करके लौंग टर्म पालिसी बनानी चाहिए तभी हम कंट्रोल कर पायेंगे वरना इसी तरह से एडहोकिज्म चलता रहेगा ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने सरकारी आंकड़ों के बारे में जो बात कही है उससे मैं पूर्ण सहमत हूं और मैं उनको और सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस काम में मैं सरकारी आंकड़ों का उपयोग तो जरूर करूंगा, लेकिन उनसे किसी तरह से गाइडेड नहीं होऊंगा । हमारे जो माननीय सदस्य और दूसरे बहुत से लोग जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं और आम जनता के सम्पर्क में रहते हैं उनसे जिन बातों का पता लगता है वे ज्यादा विश्वसनीय और ज्यादा बहुमूल्य होती हैं । मैं समझता हूं कि उनके आधार पर यदि काम किया जाय तो किसी निर्णय पर पहुंचने में और स्थिति को सुधारने में काफी सहूलियत होती है । मैं तो माननीय सदस्य से इस बात में भी सहमत हूं कि सिर्फ सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही यदि कोई काम किया जाय तो उससे बहुत भारी नुक्सान भी हो सकता है ।

जहां तक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का सवाल है और इनकी चिन्ता का सवाल है, हम सब को इसकी चिन्ता है । उसी चिन्ता को दूर करने के लिए हम लोग बहुत से कदम उठा रहे हैं । जो बहुत से सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं वे बहुत अच्छे सुझाव हैं और मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यों से बात करके और सदन में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनके आधार पर कुछ कदम उठाये जायें ताकि इस काम में जो खामियां रह गई हैं और जो बहुतसी गलतियां होती हैं उनको तत्काल सुधारा जा सके और स्थिति में हम जिस प्रकार से उन्नति लाना चाहते हैं उसको लाने में सफल हो सकें ।

माननीय सदस्य ने जो बातें फेयर प्राइस शॉप्स के बारे में और नागरिक वितरण प्रणाली के बारे में कहीं हैं वे भी ठीक हैं । यह तो आप जानते ही हैं कि पिछले 25 सालों से इस नागरिक वितरण प्रणाली को ठीक से चलाने का प्रयास किया गया है । यह एक बड़ी नाजुक चीज है और हम ऐसी स्थिति में आ गये थे कि इससे काम निकलने लग गया था । लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले तीन सालों में इस तरह की उथल-पुथल हुई कि उस सारी वितरण व्यवस्था को फिर से सेट करने में कठिनाई बहुत हो रही है । मुझे विश्वास है कि सब माननीय सदस्यों के सहयोग से उसको हम लोग जल्दी ठीक करने में असफलता प्राप्त करेंगे । इस प्रणाली की शार्टकमिंग्स के बारे में जो सुझाव उन्होंने दिये हैं वे ठीक हैं । उनके सुझावों को ध्यान में रख कर और उनसे बातचीत करके हम देखेंगे कि हम कितनों को लागू कर सकते हैं और कितनों का उपयोग कर सकते हैं और उनके कार्यान्वयन में क्या कठिनाइयां हैं । लौंगटर्म प्लानिंग करने के लिए माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं वे भी ठीक हैं । एडहोकिज्म के आधार पर कोई काम करना फायदेमंद नहीं होता है । लौंग टर्म प्लानिंग के आधार पर ही हमें काम करना होगा और

इसको ध्यान में रखना होगा । मैं समझता हूं कि इसी आधार पर हम काम करेंगे । उसके अलावा किसी दूसरे आधार पर इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है । कोई ठोस कदम उठा कर ही हम इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं ?

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट सदन के सामने रखा है वह बिलकुल अस्पष्ट है । मैं समझता हूं कि सारी स्थिति को और सारे चित्र को सही रूप में रखने का यह तरीका नहीं है । हिन्दुस्तान की जनता को और इस सदन को गुमराह करने का यह एक तरीका हो सकता है । मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं । इसमें कहा गया है कि देश में शुगरकेन का उत्पादन कम हुआ और ड्राउट और सुखाड़ की वजह से चीजों का उत्पादन नहीं हुआ और इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं । यह बात आसान है कि अपनी जिम्मेदारी से हट करके, मैनमेड दिक्कतों से हट करके प्राकृतिक प्रकोपों और कुदरती प्रकोपों पर सारा दोष डाल दिया जाय और यह कह दिया जाय कि उनकी वजह से यह सब हो रहा है । जिसको हैल्पलेसनैस कहते हैं उसका यह एक नक्शा है, एक उदाहरण है । शुगरकेन की कमी का और ड्राउट का यह असर हुआ है, यह बात सही नहीं है । शुगरकेन के उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं दिया जाता है । दूसरी बात यह है कि चीनी की जो मिलें हैं उनको अभी तक मोडर्नाइज नहीं किया गया है । चीनी मिलों का मोडर्नाइजेशन न होने की वजह से उनमें जितनी चीनी का उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं होता है । तो ये दो और वजह हैं । इसलिये जो चीनी के बारे में पूछा गया है और उसका जो जवाब दिया गया है वह साफ नहीं है । केन ग्रोअर्स को जो उचित दाम मिलने चाहिए वह नहीं दिये जाते यह इन्होंने जवाब रखा है । आज हालत यह है कि बहुत सी मिलें सिक हैं और वे माडर्नाइज्ड करने की स्थिति में हैं । इसलिये उनको सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए । चीनी के जो दाम बढ़ रहे हैं इसके लिये पहला तकाजा यह है कि सरकार इन मिलों को अपने हाथ में ले और उसके बाद और कदम उठाये । मैंने पहले ही कहा है कि उनका जवाब साफ नहीं है और भी बातें हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, बुनियादी बात यह है कि जो आवश्यक वस्तुयें हैं उनकी जो कीमतें बढ़ रही हैं उसके पीछे कारण यह है कि सरकार की कोई दाम नीति नहीं है तथा कोई दाम दर्शन नहीं है । कितना उत्पादन होना चाहिए और उपभोक्ता के पास उन आवश्यक वस्तुओं को पहुंचने का कितना अनुपात होना चाहिए, प्रोडक्शन और कंज्यूमर्स के पहुंचने के बीच कितना रेशियो होना चाहिए इस तरह का कोई आदर्श या आइडिया सरकार के पास नहीं है, इस तरह की कोई नीति सरकार के पास नहीं है । नतीजा यह होता है कि दाम बढ़ते जा रहे हैं । सरकार की ओर से कदम उठाये जाते हैं लेकिन फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकलता है । इसलिये उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार के पास कोई उचित दाम नीति होनी चाहिए परन्तु सरकार कोई ऐसी दाम नीति नहीं अपना रही है । उन्होंने कहा कि पहले तीन साल से इन्फ्लेशनरी ट्रेन्ड रहा । इन्फ्लेशनरी ट्रेन्ड पिछले तीन साल से बिगड़ा हुआ है तो फिर पिछले 25 साल, 28 साल का जो ट्रेन्ड रहा है उसको भी आपको देखना होगा । पहली बात तो यह है कि जनता सरकार के मातहत आपका कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशनरी ट्रेन्ड बढ़ा है परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि आज सरकार अपने आंकड़े देख कर बता दे कि चीनी के दाम जनता सरकार के काल में कितने स्टेबल थे परन्तु आपके आते ही चीनी के दाम भागने लगे, ऊपर चढ़ने

[श्री शिव चन्द्र झा]

लगे । आपकी सरकार के आते ही दाम भागने लगे । मैं यह नहीं कहता कि मिल-मालिकों के साथ मिल करके इलेक्शन के लिये यह किया और क्या-क्या किया, यह मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि जब कोई बात आती है तो साथ-साथ और बातें भी आती हैं । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इन्फ्लेशनरी ट्रेन्ड के लिये जो दो-तीन सालों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो तथ्य यह है कि इन पिछले दो-तीन सालों में जो ट्रेन्ड रहा है उसमें इस पर सरकार का पूरा कन्ट्रोल रहा और इसमें कोई कमी महसूस नहीं की गई । चीनी और दूसरी आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत हद तक स्थिर रहे। इसलिये यह आपका यह नेमएक्यूज जवाब है और आप अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर रहे हैं । यदि इस परिस्थिति पर आपको काबू पाना है तो समय का तकाजा यह है कि इस इन्फ्लेशनरी ट्रेन्ड पर कन्ट्रोल करने के लिये आपको दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाने चाहिए । इसके साथ ही साथ और बातों के अलावा जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है जो अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन है और जो कंसपिकुअस कंजम्पशन है उसको आप सख्ती के साथ रोकें । इस देश में कांग्रेसी राज की शुरुआत से करीब-करीब 5–6 करोड़ रुपये का कंसपिकुअस कंजम्पशन हुआ है । इसको आप सख्ती से रोकें । यदि यह नहीं रोका गया तो जो भी कदम आप बढ़ाने जा रहे हैं उसमें आप सफल नहीं हो सकते । दूसरी नीति इसमें जो है वह डीमोनोटाइजेशन की है । इसके आधार पर भी आप कन्ट्रोल कर सकते हैं । पिछले दिनों में देखा गया है करेंसी बाजार में एक्स्ट्रा क्रेडिट खूब दिया गया । आप जानते हैं कि दाम का जो फार्मूला है वह प्रोडक्शन और क्वांटम आफ मनी से संबंधित है । प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए तो क्वांटम आफ मनी भी बढ़नी चाहिए। इसका उत्पादन के साथ संबंध होना चाहिए । परन्तु उत्पादन बढ़ नहीं रहा है और क्वांटम आफ मनी बाजार में बढ़ रहा है । प्रोडक्शन तीन से साढ़े तीन प्रतिशत हर साल बढ़ रहा है पर क्वांटम आफ मनी 14 से 15 प्रतिशत हर साल बढ़ रहा है । तो एक घोड़ा तीन या साढ़े तीन मील की रफ्तार से दौड़ रहा है तो दूसरा घोड़ा 15 मील की रफ्तार से दौड़ रहा है । नतीजा यह होगा कि डिरेलमेंट होगा, दाम की गाड़ी लड़खड़ाएगी । यह नीति आप जान लें । जनता सरकार ने पूरी कोशिश दामों को कंट्रोल करने की की थी । मैं मान सकता हूं कि पूरी सफलता नहीं मिली । यदि हम लोगों का दुर्भाग्य न होता तो और भी कुछ हो सकता था लेकिन नहीं हो सका । अब आपकी जिम्मेदारी है । आप दो-तीन सालों का नाम ले कर भाग नहीं सकते, मुकर नहीं सकते । इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं इस इन्फ्लेशनरी ट्रेन्ड को कैसे आप कम करने जा रहे हैं । इसकी सफाई होनी चाहिए ।

प्रोडक्शन के बारे में शूगर का इंस्टांस मैंने दिया । पलसेज, आयल सीड्स के बारे में भी कहा । आजादी के बाद मोट तौर पर तथाकथित ग्रीन रेवोलुशन का प्रचार किया गया । खास कर के इंदिरा जी के काल में ग्रीन रेवोलूशन का बहुत ढोल पीटा गया । इसमें होता है कमर्शियलाइजेशन आफ एग्रीकल्चर । यह कैश क्राप जो हैं इनको ज्यादा बढ़ा लें । अब परिस्थिति ऐसी आ गई कि वह क्रति भी खत्म हो रही है । यह खास कर के इन लोगों के आने पर हो रहा है ।

अब फर्टिलाइजर और पानी की बात आती है । पानी की व्यवस्था न होने से उन्होंने कह दिया कि ड्राउट हो गया ।

लेकिन विज्ञान के युग में यदि यह कहा जाता है कि भारत सरकार या किसी सरकार की वजह से ड्राउट है, यह हंसी की बात हो जाती है । हर क्षेत्र में विज्ञान ने कब्जा किया है । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ।

जहां तक पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल है, यह बात ठीक है । मैं तो चाहूंगा कि इसका संचालन भी ठीक तरह से होना चाहिए । देहात में संचालन पर पूरा कंट्रोल नहीं हो रहा है । वहां पर ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग चल रही है । आपने अपने बयान में कहा कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उ.को हम पूरी मुस्तैदी से सख्ती से लागू कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं इस कानून के तहत कितने ब्लैक मार्केटियर्स, प्रोफिटियर्स और होरडर्स को सजा दी है । आप इसको किन किन इलाकों में पूरी मुस्तैदी के साथ लागू करने की सोच रहे हैं । आपको याद है चोपाटी के मैदान में पंडित जवाहरलाल नेहरु ने कहा था कि आजाद हिन्दुस्तान में ब्लैक मार्केटिंग और घूसखोरी नहीं होगी और जो भी ऐसा करेगा उसको नियरेस्ट लैम्प पोस्ट पर हैंग कर दिया जाएगा । आप बहुत दिन तक गद्दी पर रहे । सब हम लोगों को मालूम है । लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी है । इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक दाम नीति तय कर लें, इसका एक नक्शा साफ करें । पंडित जवाहरलाल नेहरु को तो आप पढ़ते ही नहीं हैं । आप डा० लोहिया का अध्ययन कर लें । दाम नीति क्या है? डा० लोहिया ने कहा कि जितने विरोधी दल के नेता हैं इन पार्टियों की बैठक बुलावें 'दाम बैठक कमेटी' में सब को ले कर एक दाम नीति निर्धारित कर लें । प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन में कितना फर्क होना चाहिए यह आप तय कर लें। जैसे मैंने पहले कहा कि शूगर इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए । आप राष्ट्रीयकरण से भागने की कोशिश न करें । इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है । जैसे और क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण किया है उसी तरह शूगर इंडस्ट्री का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए । अगर राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते तो आपको कोआपरेटिव फार्मिंग की ओर जाना पड़ेगा । डिस्ट्रिब्यूशन के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं ? इन सब बातों की सफाई आपने नहीं की है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इनको साफ करके बतावें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Mr. Pranab Mukherjee.

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): With your permission, I would like to clarify only one point which Mr. Jagdish Prasad Mathur raised in regard to sugar import. Certain questions have been tabled in this House and in the other House and I had thought that I would clarify the position while replying to the questions. But he has raised one very interesting point which has absolutely no relevance. Firstly, he said that if we had imported sugar on Government-to-Government basis from Thailand, it would have been cheaper. Perhaps, the hon. Member is not aware of the fact that Thailand does not produce that type of sugar which we use. They produce raw sugar and we purchased white sugar. And this year too, because of their own shortfall, whatever international commitments they made, they had to come out of those commitments by applying the *force majoure* clause. I do not know what Government-to-Government arrangement was made. I do not know whether they are running any parallel Government. I am the Minister-in-charge of Commerce. I did not receive any communication or information from the Thailand Government. In fact, Sir, when I

[Shri Pranab Mukherjee]

contacted certain other sugar-producing countries like Mauritius or Cuba, we were told that they were not in a position to meet their own international commitments under the international sugar agreements. So, from where he is getting this information and using this forum, I do not know. Where is the offer from Thailand? Does Thailand produce white sugar? Does Thailand export white sugar? Has Thailand exported any sugar this year? From where have you got this figure? I could explain the whole position—how much sugar has been purchased? What is the price level? What was the *modus operandi*? Again, Sir, he has brought the question of commission and all these things will come in the press tomorrow. If you want to have a full-fledged discussion, I am prepared to have it. But before that I would like to know from him as to where from he has got the information that Thailand made an offer, and that too at a Government-to-Government level. Secondly, what is the production in Thailand this year? How much have they exported? Have they produced white sugar at all the sugar that we consume? Please clarify this position.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Sir, he has not denied that sugar has been purchased from Thailand. I want to ask whether any amount of sugar that was produced in Thailand has been purchased or not. My information is that it was purchased.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Mr. Mathur, my information is 'no' because Thailand does not produce that quality of sugar which we have purchased. Then where is the question . . .

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: My question is very simple. I want to know whether any amount of sugar that was produced by Thailand has been purchased or not. That is the question.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: How many times do I repeat this? They produce raw sugar. I have purchased white sugar. So, where is the question of purchasing Thailand sugar?

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: They produce the other type of sugar and it is again converted. My question is whether any amount of sugar produced by Thailand has been purchased or not. He is still evading the answer. It has been purchased. I stick to my point.

(*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: There should be a limit for utilising this forum.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I demand Half-an-Hour Discussion on this.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: On what basis you will have Half-an-Hour Discussion?

(*Interruptions*)

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: You just now offered that you are prepared to have a discussion.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: When the questions come up, at that time, I will clarify the whole position. Mr. Mathur, in all fairness, you should rectify your position. And whosoever has briefed you, you should agree that you have been briefed wrongly. When the questions and the appropriate occasions come up, I will clarify the position.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Doesn't matter, Sir. You did offer yourself that you are prepared to have a discussion. I demand a discussion. That means, you are withdrawing your offer.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): You will have to give proper notice for it. (*Interruptions*) Order, please.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: He is withdrawing the offer.

AN HON. MEMBER: You follow the rules.

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बहुत से प्रश्न किये और कुछ बातें कहीं, मैं समझता हूं कि जो गुमराह करने की वाली बातें उन्होंने कहीं कि मैंने अपने वक्तव्य के द्वारा सदन को गुमराह करने की बात की है, यह बिल्कुल उल्टी बात है। माननीय सदस्य ने बहुत सी ऐसी बातें कहीं जो गुमराह करने वाली हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जो राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव हुए उनमें इसी तरह की बातें आम भारतीय जनता के सामने जाकर माननीय सदस्यों ने और कई उनके दलों के जो लोग हैं उन्होंने कहीं। मैं इन बातों को जानता हूं और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि इन बातों की असलीयत कि कौन किसके लिए जिम्मेदार है, हमारी आम भारतीय जनता से ज्यादा कोई नहीं जानता है और उन्होंने एक अच्छा, करारा जवाब दिया है इस बात का कि किस को वे जिम्मेदार मानते हैं आज की कठिनाइयों के लिए और आप इसके लिए मुझ से इसका जवाब चाहते हैं। वह जवाब आपको मिल चुका है। इसलिए गुमराह करने वाली जो बातें हैं, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि हम तो गुमराह नहीं करते पर जो गुमराह करने वाले लोग हैं उनको जरूर हम खोल कर सामने रख देना चाहते हैं। इसलिए जो वस्तुस्थिति है वह मैंने आपके सामने और सदन के सामने रख दी है तथा मैं समझता हूं कि वह ठीक है।

जहां तक अकाल का सवाल है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैन मेड चीज को हम अकाल के ऊपर डाल रहे हैं। माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि इस सदी के भयंकरतम अकाल से हम अभी भी गुजर रहे हैं। और उसकी कितनी भयंकर कठिनाइयां हो रही हैं, हम माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते होंगे। बिहार में भी अकाल की स्थिति है, मध्य प्रदेश में और भी ज्यादा है और दूसरे प्रदेशों में भी हैं। अकाल की स्थिति से कितना भयंकर कृषि को नुकसान होता है, किसानों को नुकसान होता है, वह भी अच्छी तरह से जानते हैं। उस पर यह कहना कि अकाल का बहाना लिया जा रहा है, यह तो ऐसी बात है जिससे कि कहने वाले का तो ज्यादा नुकसान होगा। सरकार का इससे कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि अकाल से पीड़ित लोग जो हैं, इस बात को जानते हैं कि कितना भयंकर नुकसान पूरे देश भर में हो रहा है।

गन्ने के उत्पादन में माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं। इस बात को जानते हुए कि गन्ने के उत्पादक किसान जो थे उनको पहली चोट तो उस वक्त पहुंची थी जबकि जनता पार्टी सरकार 1977 में आई, जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने की खड़ी फसल को आग लगा देनी पड़ी। इतनी भी कीमत उनको नहीं दी जा रही थी जिससे कि गन्ना काट कर वे फेंक सकें और दूसरी फसल लगा सकें। उसके कारण गन्ने का उत्पादन और जिन रकबों पर गन्ना बोया गया, वह किस तरह से कम हुआ, यह माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं।

उसके बाद चीनी का किस तरह से झंझट हुआ, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप भी माननीय उपाध्यक्ष जी सब जानते हैं कि किस तरह से जनता पार्टी सरकार आने से पहले हमारे देश में शक्कर आसानी से निर्धारित कीमत पर सब को मिलती थी, कोई कठिनाई नहीं थी। शक्कर की कठिनाई 1977 में दो आम चुनावों के बाद पैदा हुई, पहले नहीं थी। यह आन रिकार्ड है--बिल्कुल तय बात और यह

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

भी बात तय है कि उस वक्त शक्कर की कोई कमी नहीं थी । शक्कर निर्धारित कीमत पर सब को मिलती थी और शक्कर का हम लोग निर्यात भी करते थे । आज जो सब झंझट पैदा हुए हैं, अब हम उनको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं । यह बात अगर कोई कहे तो मैं माननीय उपसभाध्यक्ष जी इन तथ्यों से आपके समक्ष स्थिति स्पष्ट कर दूंगा कि यह जो बात कही जा रही है गन्ने के बारे में और चीनी के उत्पादन के बारे में, यह बिल्कुल गलत बात कही जा रही है ।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बातें जो हैं, इन पर हम गम्भीरतापूर्वक बैठ कर सोचें, राजनीति को अलग करके इस बात को सोचें । अब हमने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन करने वाले कृषकों को भी उचित मूल्य मिलेगा । चीनी मिलें जैसी थीं, पहले भी थीं, उनका उत्पादन पहले भी होता था जिससे कि हम जो हमारे घर की, भारत की जितनी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करके उसका निर्यात भी कर सकते थे और वही चीनी मिलों का आधुनिकीकरण, जैसी पहले थीं वैसी ही हैं। उनके आधुनिकीकरण और राष्ट्रीयकरण से मुझे कोई आपत्ति नहीं है । हम सब लोग उसके बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं ।

पर जो मूल चीज है, वह यह है कि हमें नागरिक वितरण व्यवस्था को इस तरह से बनाना है कि जिससे कालाबाजारी और चोरबाजारी न हो सके और जिस प्रकार से आज गन्ने के उत्पादक लोगों को, गन्ना पैदा करने वाले कृषकों को नुकसान होता है, उसको हम हटा सकें तो इस तरह से स्थिति में बहुत भारी सुधार हो सकेगा और इसी लिए उत्पादन की नीति हम लोगों की है । वह नीति बिगाड़ी गई थी । उसका हम फिर से सुधार करके इस तरह से लागू करेंगे जिससे कि फिर से इस देश में सामान्य स्थिति पैदा हो सके ।

और बहुत से जो सुझाव और दूसरी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं, उनको मैं ध्यान में रखूंगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Yes, Mr. Naidu.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Sir, what about me? How can Mr. Naidu be called? Mr. Vice-Chairman, I want to say and I want to bring to your notice that this is not the procedure. Mr. Naidu, I am not objecting to you. You can take one hour more. Mr. Vice-Chairman, you are changing the convention of this House. The Members are to be called partywise. I do not know whether Shri Jha belongs to the Bharatiya Janata Party or any other party.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: The Janata Party (J.P).

SHRI A. G. KULKARNI: I do not know. Naturally, I accommodated him and I said, it is all right. Now you are calling Mr. Naidu. This is how you want to break the convention. Let Mr. Naidu make his points. But you have not acted in the conventional manner in which this House has been going on.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): Mr. Kulkarni, we are not changing any conventions but we sometimes act according to the convenience of Members. Since Mr. Naidu has some pressing engagement and he wants to go, I am giving him the chance.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU (Andhra Pradesh): Sir, I do not want to blame this Government or the previous Janata Party Government or the previous Congress (I) Government. Sir, both this Govern-

ment and the earlier Government were depending on the Agricultural Prices Commission. They have ruined the country. The economy of the country is in doldrums. The agriculturists produce sugar, pulses, everything. Only due to these three items now, the economy of the country has been affected. Government never care for the agriculturists. They only depend upon the Agricultural Prices Commission. The Members of this Commission do not know how the paddy is grown. Such type of people are in the Agricultural Prices Commission. In other countries, they will consult the agriculturists and they will decide the prices for next year. Here, for the next year, the prices of sugarcane have not been fixed. Crores worth of sugarcane have been brunt in Meerut and other places. They could not carry sugarcane to the factories because they could not get even transport prices. This has happened. If this Government is also going to depend upon the Agricultural Prices Commission and if they are going to neglect the agriculturists, the prices would be double than what they are today. Definitely, the prices would go up. You cannot import sugar for a long-time. Only by way of a stop gap arrangement, you can import sugar. What are the steps you have taken to increase the production of sugarcane? You have not taken any steps. On the other hand, two or three days ago, you have increased the price of fertiliser by Rs. 600 per tonne. How can you bring the prices down? This is impossible. If the Government is sincere and if they want to bring down the prices, they should take some steps to reduce the prices by encouraging the agriculturists to produce more. In regard, to sugarcane, they should fix a fair price so that people can take up sugarcane cultivation and we can have enough sugar in our country. If it is necessary, you can give some subsidies to them. Unless you give some subsidies, you cannot bring the prices down. In regard to pulses, if you say you will give some reduction in land tax or announce some subsidy in regard to fertiliser, the agriculturists will produce on a larger scale sugarcane and pulses and there would not be any difficulty. Now, you are importing oil from other countries. We can export oil to other countries if you can give some subsidies or some concessions to the agriculturists to produce more. If the Government does not implement these three things, there would not be any chance of bringing down the prices. May I know from the hon. Minister whether he is going to take a practical view, leaving aside the Agricultural Prices Commission, decide matters and see that some subsidies or concessions are given so that they may produce more?

SHRI V. C. SHUKLA: Sir, we have not neglected agriculturists before and we never intend to neglect them in future also. It is well known to the hon. Member. This is our policy, which has resulted in self-sufficiency in foodgrains in our country. We have also had our policy of helping the agriculturists to produce more. We intend to follow this policy rigorously. The suggestions which the hon. Member has given are vaulable and we will certainly examine them and I can assure him that I will certainly take a practical view of the situation when tackling them.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, at the outset, I am happy to say that I am meeting my old friend again, but unfortunately, we are on the opposite benches which cannot be helped. And I am very happy to address him some questions for clarification.

Mr. Minister has taken a position that the Budget of the Janata Party presented by Mr. Charan Singh has an inflationary potential. That is true to some limited extent because every budget is an inflationary budget and in a developing country like ours it is going to happen like that. Now I would like to ask him specifically if he has gone through the relevant

[Shri A. G. Kulkarni]

price indices which have been published by the Reserve Bank of India. I am holding here a pamphlet dated May 26. This is the latest pamphlet given to me by the Parliament Library. I would ask him: Has he really gone through the indices and what is the price rise during the period from January to May? That is a very relevant point. You can reply my friends on this side. I know, my friend Pranab Mukherjee and you are very skilful and very clever Ministers, but the relevant point is: What is the price rise from January to May? I can give some figures here for your information only. The price rise for cereals is 2.8; for pulse 1.4; fibre, of course, we are not concerned; oilseeds and petroleum, I am not taking because it is an imported inflation, I do not blame this or that Government; but for sugar it is per month 2.7 and during the last five months it is 15.6. This is just for your information. It is not that you can just gloss over. It is the price rise, inevitable, and you have to accept it. Whether it is this Government or some other Government, this country and the whole world is caught in a vortex, a vicious circle, where price rise is inevitable. What I am mostly concerned with is the figure given here and you need not be complacent about it. There are the official figures published by the Reserve Bank and mind well, here there is also an item called 'cement, lime and plaster' in which they have given the figure as minus .3. This is what you call a totally distorted figure. Even if you want to build a house in Raipur you have to purchase cement at the rate of Rs. 42 to Rs. 50. per bag even though the control price is Rs. 23 or Rs. 24. So, this is the actual position of price rise and I have brought it to your notice only to that limited extent.

I would also like to bring to your notice how your Government or the Prime Minister or your Party has won the Lok Sabha elections and State elections. There the slogan given was:

"विश्वास रखिए इन्दिरा जी की बात पर, मुहर लगाइए हाथ पर।" लेकिन अब शक्कर गया है सात पर, मिट्टी का तेल गया है पांच पर।

That is a fact and that you will also have to accept, but the people have voted for your party. As a democrat I would say that they are more wise than what we talk here, but the poor man is suffering, groaning. You cannot take him for granted all the time that the *charishma* or the haunt of the Prime Minister will always come to their help. I want to bring to your notice that when you were replying to the question of sugar you were talking about the Janata Government, but I can say that all the history and chronology that was discussed here has no relevance to the Janata Government because it is very well known that right from 1975 when we were ruling, there was over-production. You might be knowing it that there was over-production. The sugarcane grower was not getting the proper price. That is why the licences were stopped and that is why my friend, Shri Mehrotra, was also bringing it to your notice that there must be a long-term policy for all the essential commodities. There cannot be a short-term solution for any problem. If there is more production of sugar, we have to have a buffer stock organisation. The Cabinet at that stage had decided to have a buffer stock organisation. But, Mr. Minister, I want to bring to your notice the malady of Indian planning. We depend more on the bureaucrats. We have to do away with this tendency. We are politicians. We must take the bull by the horn. What about onions? Onions are rotting in the streets in Maharashtra. May be, the same is the situation in the other onion growing areas. Where is the buffer stock organisation? Don't have the Civil Supplies Department, which you are now heading, as a fire-fighting apparatus. It is not a firefighting *ad hoc* arrangement. It is the long-

1 P.M.

term planning which you have to attend to in the Department. You have to supply your resourceful knowledge and give guidance to them. Have buffer stock organisation, just like in the USA or Canada where every commodity has a buffer stock organisation so that the agriculturist will not be suffering and the consumer will also not be suffering. The Government of India has to have a buffer stock organisation and long-term planning in this connection.

In the case of sugar, I am aware of what has been stated by my hon. colleague, Shri Kalraj Mishra. I know it because I am also a sugar producer in the cooperative sector. I am aware where it is purchased from. I think there is some confusion about how it is produced and how it is purchased etc. I want to know this categorically from you. During the elections period, you had released sugar out of proportion. I do not want to go into statistics, but I want to bring it to the notice of the Minister and want an assurance from him that the sugar stocks at the end of May and the sugar to be supplied upto September-October before the new crushing season starts will not reach Rs .8 per kilo. You have to assure the consumer in the country about this. My conjecture is that it will go upto Rs. 12 per kilo. You have to assure this house that the sugar, during the festival season of September-October, will be available at the price which you have mentioned. I admit that my cooperative sector has also not been fair in the case of sugar sales and making it available to the consumers. You will have to discipline not only the private sector but the cooperative sector also, because we have found out that the sugar barons have played havoc in Maharashtra during the elections—whether for the Lok Sabha or for the State Assembly. Time has come for the Government to have a long-term policy. Issue licences and have a buffer stock organisation for sugar because it will take another three years to mend the mistakes which were made by the previous regime by de-controlling sugar without controlling the monthly releases. We pleaded with the Prime Minister at that time to have monthly releases which he refused as he was very much adamant on that. And the result is sugar shortage. So I want an assurance from you. The May stocks do not portray a position that sugar will be available below Rs. 8 per kilo in this season. It may go upto a maximum of Rs. 12.

I also want to draw the attention of the Minister to the problem of cement, oilseeds, baby foods etc. Leave aside the rich elitist class consumption of talcum powder, cosmetics or tooth paste. We are not concerned with these. People are not concerned with the soap produced by Lever Brothers. We are dealing with the poverty-stricken people who only want bread and clothing. You know the malady of controlled cloth. What is happening to the controlled cloth? The mill-owners just camouflage their losses and make the Government to believe that they were not responsible and the obligation was transferred to the handloom section. The handloom section cannot do it without yarn. So, a total long-term planning is required in your Civil Supplies Department.

Sir, I do not want to take more time because it is no use goading the Minister: he himself is a very clever man. But there is one last point that I would like to make.

The Prime Minister, during her State election tours, said that they would stabilize the prices. During the Lok Sabha elections also she said they would stabilize the prices but now she says there is no magic. My dear Mr. Minister the difference between reality and populist slogans is too far and too wide. People are very clever and you have to take care of it.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SITARAM KESRI): You are more so! (*Interruptions*)

SHRI V. C. SHUKLA: Sir, it is a pleasure to answer the very interesting and very intelligent questions of the hon. Member. The suggestions he has given regarding buffer stocks and the price situation for the festival season we shall certainly take into account when we plan our future actions. I have said in my statement already that the prices have risen: I have not denied that the prices have not risen. Between January and May this year they have risen and that is causing concern to all of us. And we are trying to take steps to see how we can first stop this price rise, stabilize it and try to reduce it. There is no room for complacency. As a matter of fact, I have indicated in my statement and I agree with the hon. Member, that we should be quite concerned with what is happening, and although we have certainly said that we will try and control the prices and reduce them if possible, when we gave this assurance to the common people of the country during the elections, we also said that this is a long-term process and it is not going to be achieved in two or three months' time. But once we start the proeess, with the co-operation of the people and the co-operation of hon. Members we should be able to achieve it. This is what is our determination and this is what we have promised. These are really long-term matters, long-term planning long-term projects, long-term policies and, certainly, as the hon. Member has rightly said, there cannot be any ad-hocism about this matter. So, we will certainly closely examine these factors that he has indicated and I will assure him this much that we will do our best to see that the sugar prices are at a good level during the festival season.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. R. MORARKA): There are many more hon. Members to speak on this Calling-Attention Motion. The discussion will continue after lunch.

The House stands adjourned for lunch till five minutes past two of the clock.

The House then adjourned for lunch at eight minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at eight minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman, (Shri Sawaisingh Sisodia)** in the Chair.

SHRI DINESH GOSWAMI (Assam): Sir, before you call a new speaker to speak on the subject-matter of discussion, could we get some indication as to when we can expect the discussion on Assam to start? The Calling Attention is there and other subjects are there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): There are five or six Members still to speak on the Calling Attention Motion. We will try to see . . .

SHRI ERA SEZHIAN (Tamil Nadu): When is the Minister expected to give a reply?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): After the discussion.

SHRI DINESH GOSWAMI: Could a time-limit not be fixed about the Calling Attention and could we not stop discussion on it at a particular time?

श्री भोला प्रसाद (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, बढ़ती हुई महंगाई और जीवन की आवश्यक चीजों की कमी के सम्बन्ध में और पब्लिक वितरण प्रणाली को कामयाब बनाने के सम्बन्ध में अब तक मंत्री महोदय ने जो कुछ भी बातें कहीं हैं उससे इस बात

की गारण्टी नहीं होती है कि अभी या निकट भविष्य में बढ़ती हुई महंगाई को रोका जा सकेगा । फिर पिछला भी तजुर्बा है—चाहे मौजूदा गवर्नमेंट हो या 1977 के बाद की गवर्नमेंट हो और 1977 के पहले की जो गवर्नमेंट थी उनकी जो भी नीतियां रहीं, वे नीतियां संतुलित दाम तय करने के सिलसिले में नहीं थीं । लोगों को आवश्यक जरूरी चीजें उचित दाम पर मिलें इसके लिए जो छोटा उत्पादन करने वाले हैं चाहे वह किसान हों या छोटे आधार पर चीजें पैदा करने वाले लोग हों, उनको उनकी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलता है । इस सम्बन्ध में पहले भी ठीक ढंग से अमल नहीं किया गया और अब भी हालत वही चल रही है । मेरे ख्याल से बाजार के ऊपर जब तक बड़े-बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों का प्रभुत्व रहेगा तब तक यह आवश्यक वस्तु कानून कागजों पर ही धरा रह जाएगा । इस के द्वारा चीजों के दाम निर्धारित नहीं हो पाएंगे । मैं समझता हूं कि जब तक हमारे देश में बाजार पर बड़े पूंजीपतियों और व्यापारियों का प्रभुत्व रहेगा तब तक पब्लिक वितरण प्रणाली आंशिक रूप से ही लागू हो पाएगी और इस कारण से हमारे देश में जो महंगाई और लूट चल रही है वह चलती रहेगी और सरकार के लिए इस महंगाई पर काबू पाना संभव नहीं हो सकेगा । उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जिन चीजों की कमी है उनकी महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन जिन चीजों की कमी नहीं है उनकी भी बनावटी कमी पैदा की जा रही है और उन चीजों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं । इसके साथ-साथ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि जब किसान अपना सामान बाजार में बेचने के लिए आता है तो उस वक्त चीजों के दाम जरूर गिर जाते हैं । मसलन आप प्याज के दामों को ही ले लीजिए । अभी महाराष्ट्र के एक माननीय सदस्य ने प्याज का सवाल उठाया । आप जानते हैं कि पहले बाजार में प्याज 5 रु० किलो बिक रहा था । किसान ने सोचा कि इस साल प्याज का दाम अच्छा मिल जाएगा और उसको अच्छी आमदनी हो जाएगी । लेकिन जब किसान प्याज ले कर बाजार में आया तो उसके प्याज को कोई 10 रू० मन और 15 रु० मन तक भी लेने के लिए तैयार नहीं था । कुछ दिनों के बाद जब यह व्यापार कुछ पूंजीपतियों और बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में चला जाएगा तो फिर इसके दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे । इसी प्रकार से आप आलू की कीमतों को ले लीजिए । जिस वक्त आलू पैदा हुआ और किसान उसको बाजार में बेचने के लिए लाया तो उसको मुश्किल से 15 या 20 या 25 रु० ही मिल पाए, लेकिन जब यह काम व्यापारियों के हाथ में चला गया तो वही आलू आज दिल्ली में और दूसरे शहरों में 2 रु० प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है । हमारे देश में यह हालत हो गई है कि जब किसान चीजें पैदा करता है और उनको बेचने के लिए बाजार में लाता है तो वस्तुओं के दाम गिर जाते हैं और किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, लेकिन जब यह स्टाक व्यापारियों के हाथ में चला जाता है तो चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जब तक हमारे देश में एक संतुलित मूल्य नीति निर्धारित नहीं की जाएगी जब तक बढ़ती हुई कीमतों को रोकना संभव नहीं है । हमारे देश में जब तक बाजार के ऊपर बड़े बड़े पूंजीपतियों और व्यापारियों का प्रभुत्व रहेगा तब तक लूट चलती रहेगी । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि अगर हमें अपनी वितरण प्रणाली को कामयाब बनाना है तो जो चीजें आम लोग इस्तेमाल करते हैं उनके दाम सख्ती से तय कर दें और जो उत्पादन करने वाले हैं उनको भी उनके उत्पादन का उचित मूल्य दें । कीमतों को

[श्री भोला प्रसाद]

कम करने के लिए जब तक आप ठोस कदम नहीं उठायेंगे और जरूरी चीजों के थोक व्यापार को सरकार जब तक हाथ में नहीं लेगी तब तक आपकी पब्लिक वितरण प्रणाली कामयाब नहीं हो सकती है और न ही देश में एक संतुलित दाम नीति आ सकती है और न ही भविष्य में आएगी। उदाहरण के लिए आप कोई भी चीज लीजिए। चीनी के बारे में आप देखिए जो ...

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : यदि आप अपनी बात को संक्षेप में रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री भोला प्रसाद : यह प्रश्न इससे सम्बन्धित है इसलिए मैंने यह कहा है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सही मायनों में पब्लिक वितरण प्रणाली को अमल में लाने के लिए, जिसकी बात सरकार करती है, वह तैयार है और क्या जो आवश्यक चीजें हैं उनका स्टाक पूरे तौर पर, आंशिक तौर पर नहीं, सरकार के हाथ में लेकर इनके वितरण की व्यवस्था सरकारी दुकानों के जरिए और कोआपरेटिव के जरिए करने के लिए वह गांवों और शहरों में तयार है या नहीं? जब तक यह नहीं होगा तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता।

अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं ....

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : उदाहरण मत दीजिए आप मंत्री महोदय से सीधे सवाल पूछिये।

श्री भोला प्रसाद : उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है, चीनी की कमी के बारे में तो प्रणब बाबू जी ने कन्सलटेटिव कमेटी की मीटिंग में कहा था कि अभी हमारे यहां चीनी की खपत 52 लाख टन है और हमारे मुल्क में इसकी पैदावार 48 लाख टन है। लेकिन पैदावार 48 लाख टन होने के बावजूद देश में 20 लाख टन का स्टाक पहले से मौजूद है और उसके बाद फिर उन्होंने इसका आयात भी किया है। यह सही है कि इसमें से साढ़े छह लाख टन एक्सपोर्ट किया गया है, जो प्रणाली है उसके मुताबिक। लेकिन उसके बाद भी देश में साढ़े 61 लाख टन चीनी का स्टाक रह जाता है और खपत होती है उनके हिसाब से 52 लाख टन। तो फिर कमी का सवाल कहां उठता है। बाजार में सरकार कहती है कि हम लेवी की चीनी 65 प्रतिशत देते हैं और खुले बाजार में 35 प्रतिशत देते हैं। लेकिन खुले बाजार में जितनी भी चीनी लोगों को चाहिए वह मिल जाती है बशर्ते कि वह उसका दाम देने को तैयार हों। यह सिर्फ चीनी का सवाल नहीं है बल्कि यह हर चीज का सवाल है। इसीलिए मैं कह रहा था कि यह अमल में नहीं आ सकता है कि यदि आप इसको आंशिक तौर पर लागू करने की कोशिश करें।

श्री पी० राममूर्ति (तमिलनाडु) : आप इसी को सवाल बना दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : आप अपनी बात संक्षेप में रखें। पांच आनरेबेल मेम्बर्स सूची में हैं जिनको इस पर बोलना है।

श्री भोला प्रसाद : इसलिए मेरा सवाल यह है कि पब्लिक वितरण प्रणाली को कामयाब बनाने के लिए सरकार आवश्यक चीजों का स्टाक अपने हाथ में ले ले और उसके वितरण की व्यवस्था स्वयं करे। दूसरी चीज यह होनी चाहिए कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम देने की गारण्टी आप करें। यह बात हमेशा कही जाती है लेकिन अमल में कभी भी नहीं

आती है। यह तब तक नहीं होगा जब तक कि किसानों की उपज सरकार खुद उचित दामों पर खरीदने की व्यवस्था न करे।

श्री पी० राममूर्ति : इसी बात को सवाल बना दीजिए सरकार ऐसा करने का प्रयत्न करेगी।

श्री भोला प्रसाद : चाहे दाल हो चाहे वह आयल सीड्स या दूसरी चीजें हों जिनकी कि देश में कमी है तो इसके लिए जब तक किसानों को इन्सेटिव नहीं मिलता है, उनको उसके उचित दाम नहीं मिलते हैं तब तक इन चीजों की पैदावार नहीं बढ़ सकती है। तो फिर सरकार इन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन से कदम उठाने जा रही है ? अभी तक सरकार की ओर से जो भी दाम निर्धारित किये गये हैं वे सही नहीं हैं और उसके आधार पर यह अमल में नहीं आ सकता है। दूसरा सवाल यह है कि सरकार ने दो लाख टन चीनी का आयात किया है जिसका दाम यहां पर सात रुपये तीस पैसे प्रति किलोग्राम पड़ता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार किस आधार पर यह समझती है कि इससे वे चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर रोक लगा सकेगी ?

उपसभाध्यक्ष (श्री सावई सिंह सिसोदिया): बस काफी हो गया है, समाप्त कीजिए। यह तो कालिंग अटेंशन है इसमें भाषण देंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री भोला प्रसाद : तीसरी चीज मैं यह पूछना चाहता हूं कि चीजों का दाम सरकार द्वारा खुद बढ़ाने की नीति ठीक नहीं है। अब मान लीजिए, पेट्रोलियम का दाम बढ़ा दिया गया, खाद का दाम बढ़ा दिया गया शायद इनकी कमी हो गई थी इसलिए बढ़ाना जरूरी हो गया। लेकिन आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा कर कीमतें बढ़ाने की नीति के चलते रहने से कीमतों में कमी नहीं हो सकेगी। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि आज देश में जितनी भी करों से आमदनी होती है वह 80 प्रतिशत की जो जरूरी चीजें हैं उनके ऊपर कर लगा कर होती है। आज देश में जो बड़े बड़े मुनाफा कमाने वाले हैं, धन इकट्ठा करने वाले हैं उनकी आमदनी के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है। अब चूंकि सरकार का बजट आने वाला है क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनायेगी जिससे जनता की जो जरूरी चीजें हैं उन पर टैक्स न लगा कर कोई दूसरे तरीके से इस समस्या का हल निकाला जा सके। जब तक यह घाटे के बजट की नीति चलती रहेगी, मुद्रा का प्रसार होता रहेगा तब तक महंगाई बढ़ने की समस्या हल नहीं हो सकेगी। क्या इस सम्बन्ध में सरकार की जो आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स लगाने की नीति है जिससे कीमतें बढ़ती हैं उसमें परिवर्तन करने जा रही है जिससे आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों पर रोक लग सके। यही मेरा प्रश्न है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक करने का जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, मैंने पहले भी अपने उत्तर में कहा है कि हमारा यह प्रयास है कि हम इसे ठीक करें जिससे बहुत सी चीजें जिनको हम बाहर से मंगा कर यहां पर लोगों को देना चाहते हैं वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से लोगों को मिलें नहीं तो माल चोर-बाजारी में चलता है और लोगों को ज्यादा कीमत दे कर लेना पड़ता है। यह हमारा प्रयास चल रहा है। इस सम्बन्ध में जो सुझाव दूसरे माननीय सदस्यों ने दिए हैं जैसे आवश्यक वस्तुओं के बफर स्टाक का सुझाव दिया है जिनकी समय समय पर कीमतें बढ़ती रहती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत किसान को बाजार में कम मिलती है लेकिन उपभोक्त

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

को ज्यादा देनी पड़ती है, इसका भी हम ध्यान रखेंगे । सरकार के द्वारा उन कीमतों में वृद्धि की जाती है जिन के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता । जैसे अभी डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल की कीमतें बढ़ी हैं इसलिए इनकी कीमतें बढ़ाये बिना हमारा काम नहीं चल सकता था । इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो विचार रखे हैं उनका मैं ध्यान रखूंगा ।

SHRI P. RAMAMURTI: The Minister in his statement stated that it is only as a result of the policies that the Janata Party had pursued during the two and a half years' existence the prices have risen and that the present Government is trying to correct those policies. This was the categorical statement that he made, meaning by implication that during the period of Indian Congress rule the prices were very stable. Here I am quoting the figures from the 'Economic Survey' placed on the Table of this House by Shri R. Venkataraman, the Finance Minister, in February last. Therefore, they are not my figures. These are supplied by the Government of India itself. Here are the figures of wholesale price index. Taking 1971 as 100, the wholesale price index of all articles in 1971-72 increased to 108.2, in 1972-73 it rose to 121.5; in 1973-74 it rose to 158.0 which is nearly 27 per cent. In 1974-75 it further rose to 173. During the emergency there was a fall in the beginning to 162. But in 1976-77 it rose again to 168 and then to 182.1. This is the golden era of Indira Gandhi's rule. You must also remember that in 1966 the very first thing Shrimati Indira Gandhi did was to devalue the rupee and the prices went up like hell in 1966. It was because of this heavy price rise the students in Gujarat went on strike and the Legislative Assembly had to go. These are the facts. I am not defending the Janata Government. They also followed the same policies. The price rise today is the result of the policies the Government has been pursuing right from the time of India's independence. Prices have been continuously rising. There were one or two years when due to good monsoon fortunately the prices of foodgrains came down. This is the history of price rise and these are the facts which Shri Vidya Charan Shukla cannot dispute because these have been published by his own Government. Therefore, for him to come now and say that it is because of the policies followed by the Janata Government is to forget the fact that during his regime the prices have been rising like hell and as a result of that the Governments had to go in one or two States. Do not forget the history. Prices have been continuously rising in this country because of the activities of the speculators and as a result, our peasants, particularly the poorer sections among them, have been deprived of proper price for their produce and they have been forced to sell it at distress price at the time of harvest. Secondly, you have imported inflation into this country. You talked about price increase in the western countries. Have you only heard of western countries in this world? What about the other part of the world consisting of socialist countries where prices have been stable? You have imported inflation from the western countries and how are you going to insulate this country from that imported inflation? The only way by means of which imported inflation can be stopped is to stop getting loans from them and not to depend on multi-nationals. Then only our country can stand on its own feet. Today you have increased the price of fertilisers by 40 per cent. This is going to affect the poor peasants which again means they will be forced to resort to distress sales. Our experience during the last 30 years, since independence has shown that you cannot bring down the prices

in this country by any fiscal measure. Today the Finance Minister was saying that the Government is taking every step to bring down prices. What are those steps? You are not prepared to spell out those steps. What is the use saying "we are taking all steps"? What are those steps? This is my specific question.

When it has been proved by experience that you cannot bring down prices in this country and when it has been proved that the prices will continue to rise and our peasants will be mulcted and deprived of their proper price, is the Government of India prepared to take over the wholesale trade in all the essential commodities in its own hands and assure thereby proper price for the peasantry? Only through this process you will be able to have proper public distribution system. Only when the Government get hold of all the stocks, they can improve the public distribution system. Without that, to talk of improving the public distribution system is bunkum. It is because the stocks are not available in the public distribution system. That is the reality today. Therefore, I am asking a specific question now. Is the Government today prepared—this is the first question—to take over the wholesale trade of all the essential commodities in its own hands and arrange for a proper distribution system supervised by popular committees so that these popular committees would be a check on the retail traders? This is the first question.

Now, the second question is this: Are they prepared to stop depending on foreign loans and are they prepared not to depend on foreign investments in this country because the foreign investors, in the name of development, are looting this country? Are they prepared to make the people stand on their own legs and are they prepared to make the people patriotic enough to stand on their own legs? Are they prepared to infuse the spirit of the swadeshi movement, the movement that we started during the earlier days of our independence struggle, infuse the spirit of patriotism among the people and make all the people stand on their own legs? Is the Government prepared to do these two things? These are the two specific questions that I am asking him. Let him answer them.

SHRI V. C. SHUKLA: Sir, when I made that statement, I did not say that the price rise was due to the Janata rule. I said that it was one of the contributory factors.

SHRI RAMAKRISHNA HEGDE (Karnataka): No. That is what exactly you said.

SHRI P. RAMAMURTI: No. You said that.

SHRI V. C. SHUKLA: Everybody knows that there has been inflation in the country and inflation is not a new phenomenon and it has not come after 1977, and it has been there even before 1977.

SHRI P. RAMAMURTI: Exactly.

SHRI V. C. SHUKLA: During 1977, that is, after the 1977 elections, when the new Government came, particularly after the last Budget of Mr. Charan Singh, the inflationary tendency became very strong. That is what I had stated at that time. As far as the honourable Member's suggestions are concerned, we have looked into these before and it is not a new suggestion made by Mr. Ramamurti. These suggestions have been made from time to time and the Government has examined them and to the extent we can accept them in the present conditions of the country they have been implemented.

SHRI P. RAMAMURTI: Where?

SHRI V. C. SHUKLA: But we have to be extremely careful about this situation. It cannot be corrected by taking only the kind of action

[Shri V. C. Shukla]

that the honourable Member has suggested. But I can assure him this that we will certainly apply ourselves with great earnestness in trying to stabilise the prices to begin with and to bring them down, if possible. This will require certainly all kinds of steps which are to be made, not only these two and several other matters have to be considered. Only then we will be able to make a dent on the situation.

SHRI P. RAMAMURTI: Sir, he is not prepared to suggest one single concrete measure. He is only saying, "every measure", "every measure". What is this answer? You are only taking Parliament for a joke.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): Mr. Rameshwar Singh.

SHRI SADASIV BAGAITKAR (Maharashtra): Sir, I am just asking a question for a clarification about the specific questions that Mr. Ramamurti asked. He asked what concrete steps have been taken. The honourable Minister should enumerate the steps.

SHRI P. RAMAMURTI: Exactly. But nothing has been said.

SHRI SADASIV BAGAITKAR: It is all right if the Government does not accept Mr. Ramamurti's suggestions and one can understand that. But what steps has the Government taken? That was his specific question.

SHRI V. C. SHUKLA: If you kindly go through the statement that I have made, you will find that I have already enumerated all the steps that we have taken. These are the broad steps that we have taken and further steps are under our consideration.

SHRI P. RAMAMURTI: Wonderful!

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala): Sir, on a point of information. May I know from the honourable Minister whether the Central Government will honour its commitment made to my State, that is, Kerala, where we have a well-knit institution of civil supplies for which we want adequate quotas which the Central Government is bound to give? I would like to know whether the Central Government is prepared to give us the quota that we are entitled to and which we are prepared to distribute through the institutional methods that we have already there for so many years.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): Yes, Mr. Rameshwar Singh.

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में सदन को नहीं घसीटना चाहता जैसा कि मंत्री जी ने किया है और बार बार जब भी उत्तर दिया है तो 3 वर्ष की जनता पार्टी की सरकार का और 24 दिन की लोक दल की सरकार का जिक्र किया है । मैं तो नम्रता के साथ मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अगर देश की हालत को बिगाड़ने की जिम्मेदारी 24 दिन अगर चरण सिंह की है, या 3 वर्ष मोरारजी देसाई की है तो 30 वर्ष में जो मुल्क बिगाड़ा है इसकी जिम्मेदारी किस की है ? मंत्री जी बहुत समझदार आदमी हैं, ये मंत्री पुराने रह भी चुके हैं, इन को यह सौभाग्य प्राप्त रहा है 30 वर्ष सरकार चलाने का, मैं जानना चाहता हूं 1947 में अंग्रेज यहां से गया, उस वक्त भाव क्या था, और 1977 में जब इन की सरकार खत्म हुई जब इनका पतन-हुआ, इन की सरकार का जब खात्मा हुआ, पतन हुआ, और बहुत बुरी तरह से जब पतन हुआ, उस वक्त मुल्क कहां था ? मैं चाहता हूं उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझ को थोड़ा छेड़ा न जाए, मैं मंत्री जी को थोड़ा छेड़ना चाहता हूं और मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता कि तेल के दाम कितने बढ़ गए, चीनी के दाम कितने बढ़ गए, कागज के दाम कितने बढ़ गए . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): रामेश्वर सिंह जी, आप के छेड़ने का असर मंत्री जी में होगा कि नहीं ?

श्री रामेश्वर सिंह : मंत्री जी पर नहीं होगा तो मंत्री जी फिर रसातल को जाएंगे। इन्होंने 3 वर्ष का और ढ़ाई वर्ष का जिक्र करके सदन को बार बार गुमराह किया इसलिए मैं मंत्री जी से बहुत विनम्रता के साथ थोड़ा बहस चलाने की कोशिश करूंगा। मंत्री जी से मैं तीन चार सवाल पूछना चाहता हूं। अंग्रेज जब गया तो उस वक्त गेहूं बिकता था 30 रु० बोरी, 15 रु० क्विंटल मक्का और 12 आने किलो चीनी, और ढ़ाई रुपये बोरी सीमेन्ट। जब अंग्रेज गया उस वक्त की चर्चा मैं आप से कर रहा हूं और 30 वर्ष में *(Interruptions)* केसरी जी, धैर्य रखिए, घबड़ाइए मत, मैं इलाज अच्छी तरह से करना चाहता हूं। मैं 30 वर्ष से इलाज करता रहा हूं।

डा० भाई महावीर (मध्य प्रदेश) : ठीक कोई नहीं हुआ।

श्री रामेश्वर सिंह : और ठीक कोई नहीं हुआ। लगता है ठीक होने के लिये तैयार नहीं हैं।

SHRIMATI HAMIDA HABIBULLAH (Uttar Pradesh): He is talking of the last 30 years. This Calling Attention relates to today's position *(Interruptions)*.

श्री रामेश्वर सिंह : यही तो मैं बता रहा हूं। आप घबड़ा क्यों रही हैं? अब हम थोड़ा-सा अच्छी तरह से मरहम-पट्टी करना चाहते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : रामेश्वर सिंह जी, आप सीधे-सीधे सवाल करिये।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं कह रहा था कि ये जो दामों की बढ़ोतरी हुई वह केवल इसलिए हुई कि 30 वर्ष तक सरकार गलत नीतियों पर चली जिस का नतीजा हुआ कि आज भी उस मूल्य को नहीं बाँधा जा सका। श्रीमन्, केवल यही कहने से काम नहीं चलेगा। मंत्री जी से मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हू और बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि सच्चाई पर परदा मत डालिए। सच्चाई यह है कि जब जब मुल्क में आप को चुनाव कराना हुआ--हर 5 साल, 3 साल और 2 साल पर मध्यावधि चुनाव होते रहे हैं --आप ने पैसा पूंजीपतियों से लेने का प्रयास किया और पैसा ले कर इस काम को आप ने कराया। अभी श्रीमन्, मैं एक कोटेशन सुनाऊंगा, घबड़ाने की जरूरत नहीं है, आप के मंत्रियों के लिए कोटेशन है जो मैं सुनाना चाहता हूं : पिछले सेशन में प्रणब मुखर्जी और पहाड़िया साहब ने हमारे साथ कुछ बहस करने की कोशिश की, लेकिन मैं ने एक ही सवाल पूछा कि क्या आप ने एक पूंजीपति मिलमालिक से दस लाख रुपए ले कर चीनी का दाम नहीं बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं। आज अखबार का एडीटोरियल मैं आप को पढ़ कर सुना रहा हूं। यह मेरा नहीं है। यह आप सुनें। इस के बाद मैं आगे चलूंगा।

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : कौन सा अखबार है?

श्री रामेश्वर सिंह : आप का 'नवभारत टाइम्स' जिस से पैसा ले कर आप काम करते हैं।

श्री रामानन्द यादव : जिससे पहले आप लिया करते थे।

श्री रामेश्वर सिंह : हम को सौभाग्य ढाई बरस में 24 दिन मिला। अगर हम 24 दिन के लिए जिम्मेदार हैं--मैं कुछ बातें आगे कहूंगा, कहो तो मैं पहले कह दूं। पहले इसी प्रसंग को सुना देता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : रामेश्वर सिंह जी, मेहरबानी कर के जो सम्बन्धित प्रश्न है उस के बारे में बोलिए।

श्री रामेश्वर सिंह : सम्बन्धित प्रश्न यह है कि देश के सामने यह जटिल समस्या है। मैं यह बता रहा था कि अगर 24 दिन की चरण सिंह की सरकार और उस की नीतियों की वजह से सब कुछ हुआ है तो मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि चौधरी चरण सिंह और हम को, सारे लोक दल के लोगों को आप तिहाड़ जेल में 24 दिन की सजा दे दीजिए। ढाई वर्ष मोरारजी की सरकार रही है, ढाई वर्ष उन को जेल में डाल दीजिए। 30 वर्ष में 18 वर्ष जवाहर लाल जी रहे, जो अब नहीं हैं और 11 साल के लिए गुलजी और इन्दिरा जी को जेल में डाल दीजिए। मैं यह दंड भुगतने को तैयार हूं। अगर 24 दिन में चरण सिंह और ढाई बरस में मोरारजी देसाई की मुल्क को बिगाड़ने की जिम्मेदारी थी तो 11 वर्ष इन्दिरा जी और 18 वर्ष जवाहर लाल जी की भी जिम्मेदारी थी। यह हम ने प्रसंग में कह दिया। अब थोड़ी सुन लीजिए। अब मैं अखबार का एडीटोरियल सुना रहा हूं। अखबार कह रहा है पूंजीपतियों से आप ने पैसा लिया लोक सभा और विधान सभा चुनाव के लिए। "केन्द्रीय वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री श्री प्रणब कुमार मुखर्जी, स्वयं स्वीकार करते हैं कि मूल्यों में वृद्धि नहीं रोकी जा सकी है। चीनी, दाल, खाद्य तेल, आदि के भाव तो पहले से ही ऊंचे चले जा रहे हैं। अब अन्य खाद्यान्नों के मूल्य भी बढ़ने लगे हैं। थोक भावों का सूचांक अंक रेकार्ड तोड़ चुका है। यह प्रणब कुमार मुखर्जी का कहना है। कुल मिला कर स्थिति ऐसी बन गयी है कि इस वर्ष मानसून सामान्य रहने पर भी अभावग्रस्त इलाकों को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की समस्या अभी कुछ समय तक बनी रहेगी क्योंकि खरीफ की नयी फसल अगस्त-सितम्बर से पहले बाजार में नहीं आ सकेगी। इस समस्या का तात्कालिक समाधान तो आवश्यक है ही, दीर्घकालिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था को स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए छठी योजना को अन्तिम रूप देने का सवाल भी है।" यह उन का कोटेशन हम ने दिया।

उपसभाध्यक्ष जी, आप में इतनी सज्जनता है कि आप हमारी बात धैर्य से वे सुनें इस का प्रयास कर रहे हैं, बर्दाश्त करने की क्षमता भी उन्हें दिलवा रहे हैं। क्या उन्होंने विधान सभा के चुनाव में एक एक पूंजीपति से पैसा लेकर...

श्री रामानन्द यादव : भाषण हो रहा है।

श्री रामेश्वर सिंह : आप बिहार से आये हैं न। बिहार में आप ने 300...

श्री रामानन्द यादव : आप इस रुद्राक्ष की माला की ऐजन्टी करते थे, वह भूल गये ? कितने करोड़ रुपया आप ने लिया था ?

श्री रामेश्वर सिंह : अगर हमने लिया था तो हम को 24 दिन की सजा दे दीजिये।

श्री रामानन्द यादव : प्राइसेस पर बहस हो रही है, बजट सेशन शुरू हो गया है ?

श्री रामेश्वर सिंह : ये चाहते हैं कि वस्तु स्थिति आप के सामने न रखी जाये।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): आपको संक्षेप में इस प्रश्न के बारे में जो पूछना है वह पूछिए सीधे सीधे। यह लम्बी डिबेट नहीं है ?

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, मूल्य वृद्धि पर ही बात कर रहा हूं। मूल्य क्यों बढ़ रहे हैं ? मूल्य बढ़ेंगे जब आप पूंजीपतियों से पैसा लेंगे, जब आप मिल मालिकों से पैसा लेंगे, जब आढ़तियों से आप पैसा लेंगे और अब वे पैसा देंगे तो वे मूल्य बढ़ायेंगे क्योंकि वे पैसा कहां से देंगे। पैसा पूंजीपति तभी देता है कि जब उस को पैसा कमाने का मौका मिलता है। मैं एक उदाहरण पेश कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): इतनी लम्बी डिबेट इस में नहीं हो सकती।

5 मिनट में आप की बात समाप्त हो जानी चाहिए ।

श्री रामेश्वर सिंह : ठीक है, 5 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा । 5 मिनट आप हमको दे दीजिए । तो मैं आप को बता रहा हूं कि कल मैं मिर्जापुर से आया हूं । हमारी प्रधान मंत्री जी वहां दौरे पर गयीं थी सूखा ग्रस्त इलाके को देखने के लिये । आप देखिये कि तमाशा क्या हो रहा है। विधान सभा के चुनावों में तमाम देश भर के गुंडों को इकट्ठा कर के और उन को पैसा दे कर जब आप लोगों की जान लेने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा। गुंडा तो जब आप पैसा देंगे तभी वह किसी की जान लेगा और जब आप गुंडों का इस्तेमाल करेंगे और पूंजीपतियों का इस्तेमाल पैसा इकट्ठा करने के लिये करेंगे तो क्या होगा देश में यह बात आप सोच सकते हैं । वहां एक पोलिंग बूथ पर 14 राउन्ड गोली चली हैं जिस में उम्मीदवार के भाई और उस का एक छोटा भाई मारा गया है। तो श्रीमन्, दाम क्यों नहीं बढ़ेगा . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : यह बात मंहगाई से संबंधित नहीं है। अपने 5 मिनट में आप मंहगाई से संबंधित प्रश्न ही करिये ।

श्री रामेश्वर सिंह : 5 मिनट में यह एक मिनट का समय और जोड़ लीजिए ।

तो मैं दूसरी बात यह कह रहा था कि उदित नारायण शर्मा उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री थे और वे श्री विद्याचरण शुक्ल से कम हैसियत नहीं रखते थे । लेकिन चुनाव के 5 दिन पहले उन का मर्डर हो गया । जो उम्मीदवार लड़ रहा है उस का मर्डर हो गया । जब गुंडों को पैसा दे कर ऐसे काम कराये जायेंगे तो मुल्क में मूल्यों की वृद्धि क्यों नहीं होगी ? आज मैं आप को बतलाऊं कि जब मोरार जी भाई की सरकार थी . . .

श्री रामानन्द यादव : उपसभाध्यक्ष जी, क्या यह मंहगाई से संबंधित है ? सीधे-सीधे एलीगेशन लगाया जा रहा है . . .

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : पहले गुंडे दस रुपये लेते थे जब 20 रुपये लेते हैं यही बात वे कह रहे हैं ?

श्री रामानन्द यादव : इसी तरह से आप की लुटिया डूबी है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): अब आप के 5 मिनट में से केवल 3 मिनट बाकी हैं ।

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, हमारा दो मिनट तो रामानन्द जी ने ले लिया । ठीक है आप हम को तीन मिनट ही दीजिए, मैं इसी में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । आप को मैं बतलाऊं कि यह लोग जिस तरह से चल रहे हैं उसी के कारण उदित नारायण शर्मा जी की हत्या हो गयी है . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : यह बात आप कह चुके हैं ।

श्री रामेश्वर सिंह : तो जिस गुंडे ने उन को मारा कम से कम (*Interruptions*) तो मैं कह रहा हूं कि जब आप पैसा गुंडों, बदमाशों को बांटेंगे और पूंजीपतियों से पैसा ले कर चुनाव पर खर्च करेंगे तो उस का भार जनता पर ही पड़ेगा और इस से सीमेंट के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे, चावल के दाम बढ़ेंगे, चीनी के दाम बढ़ेंगे । श्रीमन्, यह जो दामों की वृद्धि हो रही है मैं कहना चाहता हूं शुक्ल जी से कि अगर आप इस से बचना चाहते हैं और देश को इस से बचाना चाहते हैं तो ढाई वर्ष तक जनता पार्टी की सरकार थी, हमारी सरकार थी, उस में मैं भी शामिल था, उस सरकार को अगर

[श्री रामेश्वर सिंह]

आप गुनाहगार ठहराते हैं तो क्या शुक्ल जी, आज भी आप उस से नसीहत लेने के लिये तैयार नहीं हैं क्या आप अब भी जनता के आदेश को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। अभी हमारी बहन इंदिरा जी ने कहा था कि 5 रुपये किलो प्याज बिका तथा पौने चार रुपये किलो चीनी बिकी तो चौधरी चरण सिंह की केवल 24 दिन की सरकार का इंदिरा गांधी ने ढिंढोरा पीटा था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आज 7–8 रुपये किलो चीनी बिक रही है तो जिम्मेदारी किसकी है, यह किसकी देन है ?

श्री रामानन्द यादव : चौधरी चरण सिंह के बजट की देन है। . . . *(Interruptions)*

श्री सुलतान सिंह (हरियाणा) : 21 दिन के प्राइम मिनिस्टर के बजट का असर है । . . . *(Interruptions)*

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): आप बैठिये । आप बहुत बोल चुके हैं ।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर मुल्क को इस रास्ते पर ले जाना चाहेंगे तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की राजनीति की पकड़ हमको है, कोयला 40 रुपये मन बिकेगा क्योंकि सरकार ने कोयले की खानों का नेशनलाइजेशन करके उसको तबाह कर दिया है। डीज़ल ये दे नहीं पायेंगे 5 रुपये 6 रुपये लीटर डीज़ल बिक रहा है क्योंकि सारी अर्थ व्यवस्था आपने तीस साल में बिगाड़ दी है और ढाई वर्ष हमको केवल इन समस्याओं को सुलझाने में लग गये थे क्योंकि इन्दिरा गांधी के लोग, इंदिरा गांधी के चहेते जो हल्ला करते हैं ये इंदिरा गांधी की गुलामी कर रहे हैं। . . . *(Interruptions)* । हमने मोरारजी देसाई की सरकार को कहा था कि अगर आप महगाई कम नहीं करेंगे तो आपकी सरकार नहीं चलेगी । आपकी सरकार तीस दिन में जाएगी। . . . *(Interruptions)*

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इस घमण्ड में हैं कि आप जीत गये हैं तो आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी में नहीं हैं, आप 22 प्रतिशत वोट जीत कर आए हैं, आपको जनता ने ठुकराया है। विरोधी दलों को आपसे ज्यादा वोट मिले हैं । अगर आप जनता को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो जनता आपको सबक सिखायेगी और इस कार्य में हम जनता के साथ रहेंगे . . . *(Interruptions)* इन शब्दों के साथ मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप इन बातों की पुनरावृत्ति न कीजिये। आप इतने साहसी नहीं हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ बोल सकें । आप यहां भेड़ियों की तरह से बैठे हुए हैं । हमने शेर की तरह से चलकर अपनी सरकार को और मुल्क को बचाने का प्रयास किया . . . *(Interruptions)*

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): आप बैठिये, बहुत हो चुका। समाप्त कीजिए।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं । जो पार्टी भेड़िये की तरह से चलेगी, जो लोग भेड़िये की तरह चलेंगे वह मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकते हैं । जिस मुल्क की पार्टी के अन्दर के लोगों में इंसान की तरह से दम होगा कि हम अपनी सरकार को बना या बिगाड़ सकते हैं, अपने नेता की नाक में नकेल डाल सकते हैं, तब देश आगे बढ़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं फिर कहना चाहता हूं कि शुक्ल जी आप होश में रह कर मुल्क को चलाइये नहीं तो आपको सबक जनता सिखायेगी और सबक सिखाने में हम जनता के साथ रहेंगे, उससे पीछे नहीं रहेंगे ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जब भाषण दे रहे थे तब बार-बार बीच में कुछ दूसरे माननीय सदस्य कुछ

कहते थे तो वह कहते थे कि घबराइये मत, घबरा कर मत बोलिये। मैं शान्तिपूर्वक उनकी बातें सुनता रहा। मैं भी आशा करता हूं कि मैं जो बातें कह रहा हूं वह घबरा कर बीच में व्यवधान नहीं करेंगे ...
(*Interruptions*)

श्री रामेश्वर सिंह : आप लोगों ने व्यवधान डाला है, आप ऐसी बात करेंगे तो हम भी व्यवधान डालेंगे।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपसभाध्यक्ष जी, यह बात मैं कह रहा हूं आपके द्वारा उनसे कि मेरा किसी सदस्य से मतलब नहीं। केवल माननीय सदस्य जिन्होंने यह भाषण दिया उनसे कह रहा हूं कि ...

श्री रामेश्वर सिंह : मैं आपकी बात सुनूंगा जो आप कहेंगे लेकिन आइन्दा अपने लोगों से कहिये, उनको हिदायत दीजिये कि वे हमारे बीच में न बोला करें।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मेरा उनसे निवेदन है कि वे घबरायें नहीं। बीच-बीच में व्यवधान पैदा न करें। जैसे मैंने उनकी बात को शान्ति से सुना उसी प्रकार वह भी मेरी बात को शान्ति से सुनें। अगर वह व्यवधान पैदा करेंगे तो उनका व्यवधान उन के लिये ठीक न होगा। भारतीय जनता हर पांच साल के बाद चुनाव में उत्तर देती है। आज जो लम्बा भाषण माननीय सदस्य ने दिया वह इस तरह का भाषण हर चुनाव में दिया करते हैं और जनता उनका उत्तर देती रहती है। मुझे यहां उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ; क्योंकि हमारी भारतीय जनता अपने मतदान के द्वारा हर पांच साल में दे देती है।

जहां तक पूंजीपतियों का सवाल है। पूंजीपतियों के पैसे का सवाल है पूरी भारतीय जनता इस बात को जानती है कि पूंजीपतियों का पैसा लेकर किन्होंने काम चलाया और किन्होंने नहीं चलाया। हम लोगों की आस्था यही है कि जो भारतीय जनता उचित समझती है वह करती है। 1977 में भारतीय जनता ने जो उचित समझा वह किया और 1980 में जो उचित समझा वह किया। 1952 से 1977 तक लगातार कांग्रेस को उन्होंने अपना मत दिया और चुन कर भेजा। इसलिये इस पर यहां बहस करने की आवश्यकता नहीं है। यहां मूल्य वृद्धि पर बहस हो रही है और माननीय सदस्य ने मूल्य के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा इसलिये मेरे लिये यहां उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : इनका एक प्रश्न था कि चुनाव में जो फिजूल-खर्ची हुई उसके कारण जो मुद्रा स्फीति में बढ़ोत्तरी हुई और जो एक-एक रुपये का मूल्य घटा उसके कारण जो स्वाभाविक रूप से बढ़ोत्तरी हुई उसके बारे में मंत्री महोदय का क्या कहना है यह आपने नहीं बताया।

श्री सुलतान सिंह : इसका पता तो वैद्यलिंगम रिपोर्ट से लग जाएगा।

श्री रामेश्वर सिंह : माननीय मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है। मैंने साफ इल्जाम लगाया है कि आपने पूंजीपतियों से 200 करोड़ रुपये लिये हैं जिस कारण मूल्यों में वृद्धी हुई है। क्या यह सही है इसका उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): Shrimati Rajinder Kaur.

SHRI T. ALIBA IMTI (Nagaland): Sir, most of the debate is going on in Hindi. We have been more confused.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): You can hear the translation.

SHRI T. ALIBA IMTI: My point is that the people of India have been voting the Congress Government for so many years, but yet, the prices of

[Shri T. Aliba Imti]
essential consumer goods have been going up all these years.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): I have not called you. I have called Shrimati Rajinder Kaur.

SHRI T. ALIBA IMTI: Then, in 1977, we voted for the Janata. We expected that the Janata Government would deliver the goods. But even Janata did not do better.

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): Please resume your seat. Shrimati Rajinder Kaur.

SHRI T. ALIBA IMTI: My point is that there is no use in trading mutual allegations and charges. It is useless. It will not go far.

3 P.M.

*SHRIMATI RAJINDER KAUR (Punjab): Mr. Vice-Chairman, Sir, till now he has listened to Hindi. Now he will listen to Punjabi also. The discussion is about the fact that the prices are rising. There are no two opinions about it. But what are the reasons for the price rise? Different speakers have assigned different reasons therefor. The rise in the price of crude oil has been mentioned as one of the reasons for the price hike. The price rise has also been attributed to the foreign loans that we receive. It increases inflation. Third reason has been mentioned that the party that has won had taken money from the capitalists, industrialists and traders and, in order to compensate them, they have been permitted to raise prices.

The fact is that all political parties take money from big industrialists and big traders. The rich man, the industrialist, never gives charity. He always invests. He may give ten lakhs to the winning party five lakhs to the losing pary and two lakhs to other lesser parties. But they do give donations to all the parties.

The party which wins is doubly blessed. What happens is that these traders never give donations. If they donate ten lakhs they earn ten crores. I am reminded of an instance. In Punjab, before the 1971 elections, I was sitting with some Members of the Punjab Cycle Dealers Association. The elections were at hand. they told me that the Punjab Cycle Dealers Association had given 35 lakhs of rupees to the Congress Party. I asked them as to how they, being small traders, would make up for that amount. They replied that each of them had donated according to his capacity,—a thousand and odd rupees—and that won't make much of a difference as they increase the price of a cycle tyre by two rupees and that of a cycle rickshaw tyre by three rupees. As a matter of fact the very same thing happened after the elections. The prices of cycle and cycle rickshaw tyres were raised by rupees two and rupees three, respectively.

This brief discussion is not going to solve the problem. A man who spends ten lakhs over his election as an MLA, certainly does not do so for the benefit of his salary and allowances as an MLA which total upto Rs. 2,000 a month. He does not do it for the service of the people either. After becoming a Member, his first duty is to serve his own interests and serve the people thereafter.

Leave aside these Members. Take the case of Ministers. With a few exceptions like Mr. Kidwai, which Minister does not own any property or assest after he ceases to be a Minister? A Minister leaves enough for his seven generations. The only difference is that these Ministers get money from the Industrialists and traders who in turn exploit the people. The Janata Party has been saying that an MP, a Minister or a person otherwise in public life shall be liable to declare his assets at the time of assuming office so that on his relinquishing that office, if some

*English translation of the original speech in Junjabi.

property is found to have been earned through corrupt means it could be confiscated by the Government. Some way must be found out.

I had recently been to Pakistan. There an unskilled labourer gets Rs. 25 a day and a skilled labourer gets about Rs. 100 to Rs. 125 a day as wages. They are selling cloth at much cheaper rates. Why can't we do that? Because we get donations from the textile industry, we allow them to raise cloth prices. Mr. Murthy and others raised certain points I would also like to ask specific questions although I know they won't be replied to.

What specific steps Government propose to take to bring down the prices? At least they should ask their Ministers and Members to declare their assets so that we could know how much money they make at the end of their term. We contest elections in the name of poor. But who fights elections for the sake of the poor? After all, where this inflation is going to end? If they check corruption in their own party, it would act as a deterrent. Thank you very much.

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने जो भाषण दिया उपसभाध्यक्ष महोदय, उसका कोई कीमतों से मतलब नहीं है । उन्होंने एक बात कही कि इस तरह से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसके बाद ट्रेडर्स और दूसरे लोगों को उसका फायदा दिया जाता है जिसका कि कीमतों पर असर पड़ता है । यह बात कांग्रेस शासन में होती नहीं है । यह बात हो सकती है कि किसी अन्य शासन में या राज्यों में यह होती रही हो । माननीय सदस्या को हो सकता है कि पंजाब में इसका अनुभव रहा हो । मेरा कहना है कि हम लोगों के शासन में, जहाँ तक मैं जानता हूं ऐसा हुआ नहीं है और अगर कहीं हो जाये तो इसे हम बहुत दृढ़तापूर्वक रोकते हैं और इससे बचते हैं । इसलिये मैं माननीय सदस्या को आश्वासन देता हूं कि इस बात की वे चिन्ता न करें कि इस कार्य से आगे चल कर हम लोगों को कीमतों को बढ़ने से रोकने में कोई असफलता मिलेगी ।

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) : माननीय मंत्री जी से सिर्फ मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं । महोदय, आपको याद होगा कि पहले चीजों पर दाम छपा करते थे । आप कपड़े की ही बात ले लीजिये । कपड़े पर दाम छपा करते थे एक्स मिल प्राइस, उसके नीचे एक्साइज ड्यूटी और फिर उसके नीचे रिटेल प्राइस । आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि इन चीजों पर आज जो दाम छप रहे हैं उसमें हकीकत यह है कि व इस प्रकार छप रहे हैं एक्स मिल प्राइस, उसके नीचे एक्साइज ड्यूटी, उसके नीचे मैक्सिमम प्राइस नाट एक्सीड देन देट (अर्थात् अधिकतम मूल्य) और फिर लोकल टैक्स ऐक्स्ट्रा, यह इन चीजों पर छपने लगा है, मैं आपको अगर आप चाहें तो इसका सबूत भी दे सकता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : आप सवाल पूछिये ।

श्री लाडली मोहन निगम : 3.41 पैसे मीटर का बना हुआ कपड़ा चाहे बम्बई में बना हो या मध्य प्रदेश में बना हो, उस पर 15 पैसा एक्साइज ड्यूटी है वह आज 8.24 पैसे मैक्सिमम प्राइस पर बिक रहा है । उपसभाध्यक्ष महोदय, आपको अंदाजा होना चाहिए कि साढ़े तेरह मीटर फी आदमी के हिसाब से हिन्दुस्तान में कपड़े की खपत है । इस हिसाब से दो रुपया मुनाफा भी अगर इन मिल मालिकों का लगा लें तो एक साल में 27 रुपये प्रति मीटर कपड़े पर मुनाफे की शक्ल में मिल मालिक लेता है । आज हिन्दुस्तान की आबादी 65 करोड़ है । मैंने हिसाब लगाया है कि साढ़े सत्तरह सौ करोड़ रुपये साल भर में कपड़े पर लूट है । तो क्या इसके लिये आपके पास कोई योजन है और प्राइम स्टेपिंग के मामले में आप क्या

[श्री लाडली मोहन निगम]

करने जा रहे हैं। अगर आप उसकी कोई योजना नहीं बना सकते और उसके दाम नीचे तय नहीं कर सकते तो तब तक मामला ठीक नहीं होगा। यह आप निश्चित रूप से मानिये कि जब तक दाम नीति तय नहीं की जाएगी आप मंहगाई दामों की उछल कूद नहीं रोक सकते हैं, यही मेरा निवेदन है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): We go to the next item Statement by Minister.

DR. BHAI MAHAVIR: I want to ask some clarifications. My name is there in the list.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): After this statement by the Minister, we will go to the Special Mentions.

DR. BHAI MAHAVIR: I am referring to the Calling Attention. I am seeking your permission to ask one clarification on the Calling Attention subject because my name is there in the Calling Attention Notice but since only one Member was permitted from each party, my turn did not come. But I want to ask one little clarification, just as you have permitted some other Members.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): The list has been exhausted. There are other items on the List of Business. We have to take them up.

DR. BHAI MAHAVIR: Sir, we are just beginning a new item. The question that I wish to ask is, in the last Session we came across a little confusion because two Ministers of the Government were making two different statements on the question of sugar. While Mr. Pranab Mukherjee made an annauncement here that the country would export the committed amount of sugar to other countries, at the same time reports had appeared of the Home Minister having said that we were going to import sugar into the country, and the Secretary of the Agriculture Ministry, Dr. Swaminathan had also said that. When this thing came up in the House, Mr. Pranab Mukherjee, the hon. Leader of the House, said that the Ministers statement was to be taken and the officers were not responsible to the House. So we remained in a sort of confusion, not knowing whether we are exporting sugar or whether we are importing sugar or whether we are doing both. It appears, Sir, that we are doing both.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): What is your question?

DR. BHAI MAHAVIR: The question, there, Sir, is this confusion a part of Government's policy? Mr. Pranab Mukherjee has again, a few days back, said to the pressmen that we should not lose our place in the export market—which means we should keep on honouring our commitments to export sugar.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): Please be brief. If you want to know anything you can just directly put the question.

DR. BHAI MAHAVIR: So the question directly is: Are we importing sugar, or are we exporting sugar, or are we doing both? Secondly, if we are importing sugar, is it a fact that one ship carrying our own sugar was turned midway, on the high seas back and we re-purchased our own sugar at an exorbitant price? Has this particular incident come to your notice? Because it is common belief. many people have been saying it that there has been a loss to the country because of this transaction. The third point I want to know is whether it is a fact that the price at

which we bought sugar in the London market (Rs. 732 per quintal) is almost double the price of Indonesian sugar which is Rs. 400 per quintal. If that is so, has the country not allowed an exorbitant margin of profit to the middlemen? Sir, if it is a fact that these brokers who have unndertaken to supply sugar to us would be able to supply it only in November, then our own sugar for the season would have arrived in the market and it is therefore that our exporters are insisting for permission to export one million tonnes of sugar because they think that we shall have sufficient supplies by then in the market. If that is so, it becomes an all the more perplexing situation. Why should we be needing to import all that stuff in November when our own market supplies will be there in October? I would like to have clarifications on these points.

SHRI V. C. SHUKLA: Sir, I can say positively that the allegations he has made are wild and are absolutely incorrect.

DR. BHAI MAHAVIR: Please speak into the mike.

SHRI V. C. SHUKLA: But this Ministry is not handling the import or export of sugar. So, if he really wants details of any transaction, he should table the question, ask the question, from the relevant Minister and, I am sure, all the relevant particulars will be supplied to him. I can state on good authority that the allegations levelled by him are absolutely incorrect.

DR. BHAI MAHAVIR: Does it mean that the left hand does not know what the right hand is doing? This is a strange situation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): I won't allow any furter discussion on this.

DR. BHAI MAHAVIR: Sugar is a basic thing and he is not able to say whether we are importing or exporting or doing both.

STATEMENT BY MINISTER

Increase in the prices of petroleum products

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI DALBIR SINGH): Sir, hon. Members would kindly recall . . .

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal): Is it about Calling Attention?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): He is making a statement.

SHRI LAL K. ADVANI (Gujarat): Sir, what is this?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): Mr. Minister, do you want to read the whole thing? It is a big one. Will you lay it on the Table of the House?

SHRI DALBIR SINGH: Sir, if you want, I can lay it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SAWAISINGH SISODIA): You may. You do not have to read it then.

SHRI JAHARLAL BANERJEE (West Bengal): It is too late now.

उपसभाध्यक्ष (श्री सावाई सिंह सिसोदिया) आप पटल पर रखने की बात कहिए।

SHRI DALBIR SINGH: Sir, details are given in this. So, with your permission, Sir, I place this statement on the Table of the House; and along with that I also place the following documents on the Table of the House, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the